● वर्ष-2
● अंक-275
रायपुर, रविवार
09 जुलाई 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

अवकाश सूचना

समाचार पचीसा के कार्यलय में 09 जुलाई रविवार अवकाश रहेगा। समाचार पचीसा का अगला अंक 12 जुलाई मंगलवार को प्रकाशित होगा।

चुनाव में जल उठा पश्चिम बंगाल

चुनाव गोलियों से नहीं बल्कि मतपत्रों से होने चाहिए: राज्यपाल बोस

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को महत्वपूर्ण त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए मतदान के दौरान व्यापक हिंसा देखी गई। इस दौरान कम से कम एक दर्जन लोगों की मौत हो गई, कई मतदान केंद्रों में तोड़फोड़ की गई और मतपत्रों में आग लगा दी गई। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने झड़पों को रोकने में विफल रहने के लिए केंद्रीय बलों को दोषी ठहराया, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया। स्थिति का जायजा लेते हुए राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने लोगों से मिलने के लिए विभिन्न जिलों का दौरा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इससे हम सभी को चिंता होनी चाहिए। यह लोकतंत्र के लिए सबसे पवित्र दिन है... चुनाव गोलियों से नहीं बल्कि मतपत्रों से होने चाहिए।

9 जून को राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा की है, तब से पूरे पश्चिम बंगाल में हिंसक झड़पें हुई हैं। परिणामस्वरूप, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 6 जुलाई को 10 दिनों के लिए राज्य भर में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। 11 जुलाई को चुनाव परिणाम की घोषणा लोगों और निर्वाचित पंचायत सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए।

हिंसा में 11 लोगों की मौत

शुक्रवार रात से लेकर अब तक हुई चुनाव संबंधी हिंसा में 11 लोग मारे गए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मारे गए लोगों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के छह सदस्य, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) के एक-एक कार्यकर्ता और एक अन्य व्यक्ति शामिल है, जिसकी पहचान उजागर नहीं हो सकी है। अधिकारियों के मुताबिक, हिंसक झड़पों में कई लोग घायल भी हुए हैं। इसके अलावा, राज्य के कई हिस्सों में मतदान केंद्रों पर मतपेटियों को नष्ट किए जाने की खबरें हैं।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव

पंचायती राज प्रणाली के तीन स्तर हैं- ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर), मंडल परिषद या ब्लॉक समिति या पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर), और जिला परिषद (जिला स्तर)। पश्चिम बंगाल में 3,317 ग्राम पंचायतें और कुल 63,283 पंचायत सीटें हैं। ग्राम पंचायत चुनाव केंद्रों की संख्या 58,594 है।

राजनीतिक दलों ने हिंसा की निंदा की

चुनाव संबंधी हिंसा में अपने छह समर्थकों को खोने वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने विपक्षी दलों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और मतदाताओं की सुरक्षा करने में विफलता के लिए केंद्रीय बलों की आलोचना की। राज्य की मंत्री शशि पांजा ने पूछा, भाजपा, माकपा और कांग्रेस ने साठगांठ की थी और केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी। आखिर वे कहां तैनात हैं? तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। केंद्रीय बल कहां हैं?'' दूसरी ओर, कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर चौधरी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के 'गुंडे' खुलेआम घूम रहे हैं और लोगों का जनादेश लूट लिया गया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सचिव मोहम्मद सलीम ने दावा किया कि केंद्रीय बलों की उचित ढंग से तैनाती नहीं की गई है।

भाजपा ने की राष्ट्रपति शासन की मांग

भाजपा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की मांग की है। हिंसा को लेकर भाजपा ने कहा कि बंगाल में सत्ताधारी पार्टी बैलेट पर नहीं बल्कि बुलेट पर भरोसा करती है इसलिए राज्य की यह स्थिति है। भाजपा का दावा है कि बाहरी घुसपैठिए, असामाजिक तत्त्व और तृणमूल के गुंडों को ममता बनर्जी पनाह दे रही हैं। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यह कोई चुनाव नहीं है...यह जंगल राज है। केंद्र सरकार फैसला ले...मेरी मांग है, अगर राष्ट्रपति शासन नहीं है तो ममता बनर्जी को सीएम रहने दें...चुनाव लड़कर हम उन्हें हटा देंगे लेकिन नागरिकों की सुरक्षा के लिए धारा 355 लागू होनी चाहिए।

निशीथ प्रमाणिक के सवाल

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने कहा कि यह पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या और एक चुनाव आयोग का किसी एक पार्टी के लिए काम करना लोकतंत्र के सख्त ख़िलाफ़ है। बंगाल में चुनाव घोषणा से लेकर नतीजे की घोषणा तक जितनी भी मृत्यु होंगी उन सभी मृत्यु की ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग और वहां की सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में एक ही फेज और बिना केंद्रीय बल की तैनाती के चुनाव कराने का निर्णय लिया था। हम इसके ख़िलाफ़ कोर्ट गए और कोर्ट ने भी इसको माना। लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग है। केंद्रीय बल को सिर्फ पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए रखा गया और किसी भी बूथ पर केंद्रीय बल के जवानों को तैनात नहीं किया गया।

रवि शंकर प्रसाद का वार

सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि भाजपा इस हिंसा की निंदा करती हैं। उन्होंने कहा कि ममता जी आप बैलेट बॉक्स ले आईं। उन बैलेट बॉक्स को छीना, तालाब में फेंका, किसी में स्याही डाली जा रही है। ममता जी आपकी सरकार के लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता की परीक्षा हो रही है।

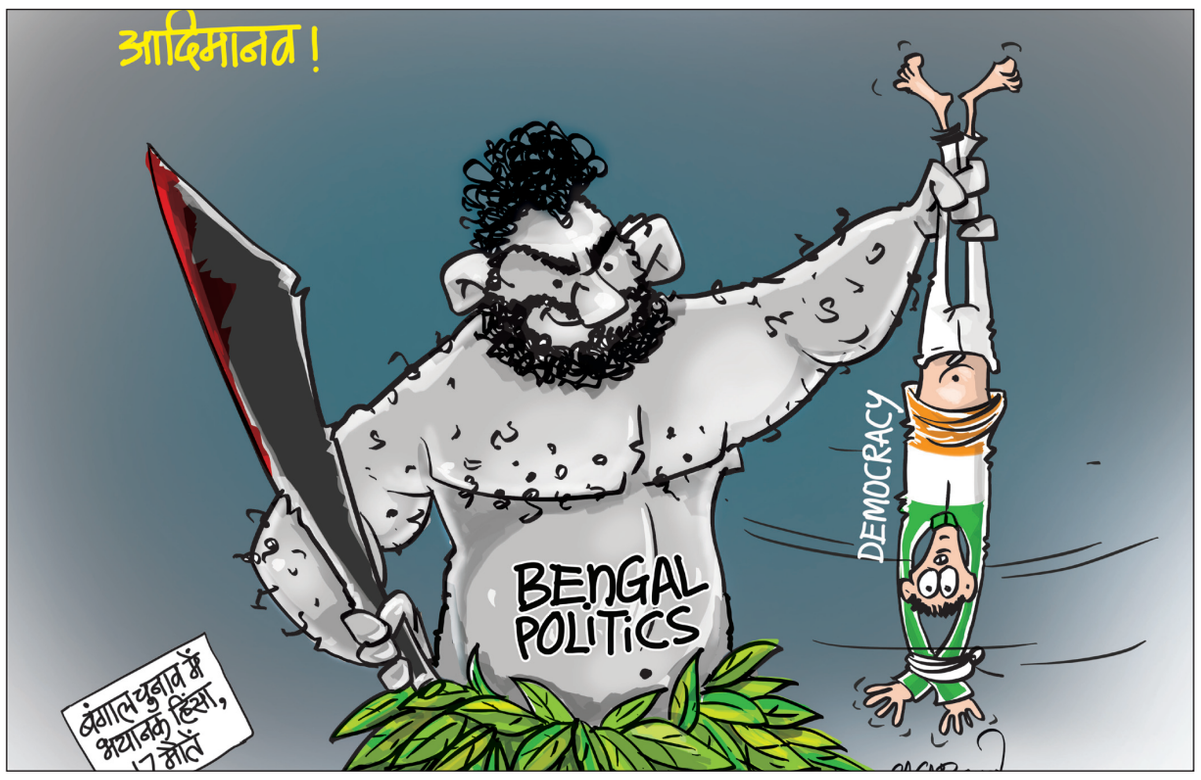

लद्दाख में भारत कर रहा बड़ी युद्ध अभ्यास

- **टी-90 और टी-72 टैंक और धनुष को किया गया तैनात**

नई दिल्ली। लद्दाख से चीन को परेशान करने वाली खबर सामने आई है। पूर्वी लद्दाख में सेना की बड़ी वॉर एक्सरसाइज हो रही है। इंडियन आर्मी के घातक टैंक एक्शन में दिखे। सिंधु नदी को पार करते दुश्मन देशों के टैंक पर निशाना साधते दिखे। 16 हजार फीट की ऊंचाई पर युद्धाभ्यास किया जा रहा है। किसी भी हालात से निपटने के लिए ये सारी प्रैक्टिस की जा रही है। लद्दाख से आई दुश्मन के ठिकानों को नेस्तोनाबूद करने वाली ये तस्वीरें विरोधियों के मोरॉल को डॉउन करने के लिए काफी हैं। जरा कल्पना कीजिए 16 हजार फीट के ऊंचाई के साथ जब टैंक आगे बढ़ते हैं तो उससे इलाके से लगने वाले पड़ोसी देश की दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं।

सिंधु नदी पार करते टी-90 और टी-72 टैंक

जियो पॉलिटिकल लेवल पर भारत का जो क्लियर स्टैंड है वो बॉर्डर पार वालों को अपना मैसेज कन्वे करने और बताने का वो साफ लग रहा है। ये एक्सरसाइज न्योमा-पूर्वी

लद्दाख में किया जा रहा है। नए नए हथियारों और वाहनों के साथ सेना सिंधु नदी के किनारे 16 हजार फुट की ऊंचाई पर एक्सरसाइज कर रही है। इसके वीडियो में आप देख सकते हैं कि टी-90 और टी-72 टैंकों को नदी पार करते हुए। आर्मी ने हाल ही में भारत में बनी स्वदेशी धनुष होवित्जर को शामिल किया है। यह बोफोर्स तोप का एडवांस्ड वर्जन है।

16 हजार फुट की ऊंचाई पर अभ्यास

सेना के अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के अभ्यास आकस्मिक परिस्थितियों की तैयारी के लिए किए जाते हैं, जहां उन्हें इस क्षेत्र में घाटियों के मार्गों का उपयोग करके भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश करने पर विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है। भारतीय सेना दुनिया की उन चुनिंदा सेनाओं में से एक है जो 16,000 फीट तक की ऊंचाई पर और बड़ी संख्या में टैंकों का संचालन करती है। जब चीनी सेना ने अपने प्रशिक्षण अभ्यास सैनिकों को हटाकर पूर्वी लद्दाख सेक्टर में आक्रामकता दिखाना शुरू कर दिया, तो भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहन लाए, जिसमें बड़ी खुली घाटियाँ हैं जो टैंक युद्ध के लिए बहुत अनुकूल हैं। पहले, भारतीय सेना पाकिस्तान के मोर्चे पर पंजाब सेक्टर में बड़े पैमाने पर इस तरह के अभ्यास करती थी क्योंकि ऐसा माना जाता था कि केवल मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में ही टैंक युद्ध होंगे लेकिन बाद में मानसिकता बदल गई।

टैंकों के साथ ब्रिगेड और अन्य संरचनाओं को 2013-14 में पूर्वी लद्दाख में बल में शामिल किया जाना शुरू हुआ, लेकिन 2020 में गलवान घाटी संघर्ष की घटना के बाद संख्या कई गुना बढ़ गई। उस घटना के बाद भारतीय वायुसेना के सी-17 और इल्युशिन-76 परिवहन विमान बड़ी संख्या में रेगिस्तानों और मैदानों से टैंक और बीएमपी लाए थे सेना ने क्षेत्र में बख्तरबंद ताकत को इस हद तक मजबूत कर दिया है कि वे प्रतिद्वंद्वी के किसी भी दुस्साहस से निपट सकते हैं।

प्रमुख समाचार

कांग्रेस का मतलब लूट की दुकान, झूठ का बाजार: मोदी

नई दिल्ली। अपने राजस्थान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में जनसभा को संबोधित करते कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि आने

वाले चुनाव में भाजपा की यहां जीत होगी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि आपका ये उत्साह बताता है कि राजस्थान में केवल मौसम का ही पारा नहीं चढ़ा है, बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का पारा भी चढ़ चुका है और जब जनता का पारा चढ़ता है तो सत्ता की गर्मी उतरते और सत्ता बदलते भी वक्त नहीं लगता। मोदी ने कहा कि हम दिल्ली से योजनाएं राजस्थान में भेजते हैं, लेकिन यहां जयपुर में कांग्रेस का पंजा उस पर झपट्टा मार देता है। कांग्रेस को राजस्थान के लोगों की परेशानी से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में राजस्थान को सबसे टॉप पर होना चाहिए था, लेकिन ये धीमा करने वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल है। आज देश के 130 से ज्यादा जिले ऐसे हैं, जहां शत-प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंचा है, लेकिन इनमें से राजस्थान का एक भी जिला नहीं है।

कांग्रेस ने भाजपा को परिवारवाद पर दी चुनौती

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शनिवार को वंशवाद की राजनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार हमलों का जवाब देते हुए उन्हें यह घोषणा करने की चुनौती दी कि भाजपा किसी भी ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन

नहीं करेगी जिसे वह परिवार द्वारा संचालित मानती है। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार सेल के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री को राजनीति में परिवारों और वंशवाद के बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए, उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक परिवारों के लोगों से भरी हुई है। प्रधानमंत्री अगले लोकसभा चुनाव से पहले सामने आएं और घोषणा करें कि भाजपा किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, जो उनके अनुसार एक परिवार संचालित पार्टी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि साहस दिखाने दो...आत्मविश्वास दिखाने दो। आज उनके पास (लोकसभा में) 303 सीटें हैं। उन्हें यह घोषणा करने से कौन रोकता है कि, एक नीति के रूप में, भाजपा एक परिवार द्वारा संचालित पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी? उसे एक उदाहरण स्थापित करने दीजिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ज्ञानी को ज्ञानी मिलते हैं।

मिजोरम: भाजपा में शामिल होंगे एमएनएफ के बेइछुआ

आइजोल। मिजो नेशनल फ्रंट के पूर्व नेता के. बेइछुआ इस साल के अंत में होने वाले मिजोरम विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने पिछले साल मंत्री पद से

इस्तीफा दे दिया था। एक भाजपा नेता यह जानकारी दी। भाजपा के मीडिया संयोजक जॉनी ललथनपुइया ने शनिवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि वरिष्ठ मारा नेता ने कहा कि चुनाव की तारीखों के एलान के बाद वह औपचारिक रूप से भगवा खेमे में शामिल हो जाएंगे। भाजपा के टिकट पर दक्षिण मिजोरम के सियाहा से चुनाव लड़ेंगे। सामाजिक कल्याण, आबकारी और पशुपालन सहित कई विभागों को संभालने वाले बेइचुआ ने पिछले साल 13 दिसंबर को जोरामथांगा के मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। एक दिन पहले उन्हें कथित तौर पर मुख्यमंत्री ने ऐसा करने के लिए कहा गया था। सत्तारूढ़ एमएनएफ ने उन्हें 25 जनवरी को मारा स्वायत्त जिला परिषद के अध्यक्ष एन वियाखू के साथ पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी के प्राथमिक सदस्य के रूप में निष्कासित कर दिया था।

25 प्रतिशत तक कम हो सकता है इन ट्रेनों का किराया

नई दिल्ली। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई है। रेलवे बोर्ड के एक आदेश में कहा गया है कि भारतीय रेलवे पूरे भारत में चलने वाली सभी ट्रेनों में एसी चेयर कार और एक्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25 प्रतिशत तक की कटौती करेगा। इसे वंदे भारत एक्सप्रेस के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। इस कदम से वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, अनुभूति और विस्टाडोम कोच जैसी ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिभोग के आधार पर लाभ मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने कहा कि किराया परिवहन के प्रतिस्पर्धी साधनों पर भी निर्भर करेगा। यह योजना अवकाश या त्योहार स्पेशल के रूप में शुरू की गई विशेष ट्रेनों पर लागू नहीं होगी। छूट का तत्व मूल किराये पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक होगा। अन्य शुल्क जैसे आरक्षण शुल्क, सुपर फास्ट सरचार्ज, जीएसटी इत्यादि, जो भी लागू हो, अलग से लगाए जाएंगे। अधिभोग के आधार पर किसी या सभी वर्गों में छूट प्रदान की जा सकती है। पिछले 30 दिनों के दौरान 50 फीसदी से कम अधिभोग वाली ट्रेनों को ध्यान में रखा जाएगा। छूट की मात्रा तय करते समय परिवहन के प्रतिस्पर्धी साधनों का किराया मानदंड होगा।

शिंदे को इस्तीफा देने कहा; उनके गुट के 20 संपर्क में: आदित्य

नई दिल्ली। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संबंध में बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सीएम को शिंदे को इस्तीफा देने के

लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि इससे संकेत मिलता है कि अजित पवार और राकांपा के आठ अन्य विधायकों के उनके एक साल पुराने राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने से सीएम की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। अजित पवार वर्तमान में शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के साथ उपमुख्यमंत्री का पद साझा करते हैं। आदित्य ठाकरे ने मीडिया से कहा, मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है और (सरकार में) कुछ बदलाव हो सकता है। ठाकरे की यह टिप्पणी उन खबरों के बीच आई है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बागी अजित पवार और उनके समर्थकों के सरकार में शामिल होने के बाद भाजपा एकनाथ शिंदे समूह को दरकिनार कर रही है। हाल ही में शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया था कि राकांपा नेता अजित पवार के राज्य सरकार में शामिल होने के बाद से शिंदे के गुट के करीब 20 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं।

दिमाग के अंदर मांस को खा जाता है अमीबा नाम का एकजीव

हिमांशु मिश्रा

केरल में हुई एक 15 साल के किशोर की मौत पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। मृतक अलप्पुझा जिले के पनावल्ली के रहने वाला था। किशोर अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस बीमारी ग्रसित था। इस बीमारी को पॉम भी कहा जाता है। इस बीमारी के होने के पांच से दस दिन के अंदर ही इंसान दम तोड़ देता है। ये बीमारी अमीबा नाम के एक जीव से होती है। इंसान के शरीर में पहुंचते ही ये जीव उसके दिमाग पर हमला करता है। दिमाग के अंदर के मांस को पूरी तरह से ये जीव खा जाता है। बच्चे की मौत पर केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज का बयान भी सामने आया। उन्होंने बताया कि ये बीमारी नई नहीं है। पहले भी इस तरह के पांच मामले सामने आ चुके हैं। पहली बार 2016 में और उसके बाद 2019, 20 और 22 में ऐसे मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, इस बीमारी की चपेट में आने वाले सभी मरीजों की मौत हो गई है।

अमीबा है क्या?

डॉ. अग्निहोत्री ने कहा, दिमाग के अंदर घुसकर मांस खा जाने वाले इस जीव का नाम अमीबा है। इसे नेग्लरिया फाउलेरी भी कहते हैं। ये अमीबा धीरे-धीरे दिमाग की टिश्यू को नष्ट कर देता है। संक्रमण फैलने से दिमाग में सूजन आने लगती है।

डॉ. अग्निहोत्री के अनुसार, अमीबा एक कोशिकीय वाला जीव है, जो खुद से ही अपना आकार बदल सकता है। ये आमतौर पर तालाबों, झीलों और धीमी गति से बहने वाली नदियों में पाए जाते हैं। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने यानी प्रिमिटिव जीवों में से एक है। ये एक एककोशिकीय जीव बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से अलग होता है।

नाक के जरिए शरीर में दाखिल

डॉ. अग्निहोत्री के अनुसार, %ये अमीबा आमतौर पर तब इंसान को अपना शिकार बनाता है, जब कोई नदी, तालाब, पोखरा, झील

के पानी में गोता लगाता है। अगर कहीं गंदे या जमे पानी का कोई इस्तेमाल होता है तो उससे भी इस संक्रमण के फैलने की संभावना होती है। ज्यादातर ये जीव गर्म पानी में मिलता है।'

'संपर्क में आने वाले इंसान के नाक रास्ते ये शरीर में घुस जाता है। इसके बाद ओल्फेक्ट्री नर्व से चिपक जाता है। इसी नर्व की मदद से इंसान किसी गंध या खुशबू की पहचान करता है। ओल्फेक्ट्री नर्व दिमाग की सबसे निचली हड्डी यानी क्रिबीफॉर्म प्लेट से जुड़ी होती है। इस रास्ते से अमीबा खुशबू को पहचाने वाली नर्व तक पहुंचता है। इसके बाद ये दिमाग में पहुंचकर चिपक जाता है और धीरे-धीरे ब्रेन टिश्यू को नुकसान पहुंचाने लगता है। दिमाग में अमीबा ट्रोफोजोइट बना लेता है। मतलब की इंसान के दिमाग को चूसकर अमीबा अपना पेट भरता है।

इसके क्या लक्षण होते हैं?

डॉ. अग्निहोत्री ने बताया कि अमीबा इंसानों के शरीर में घुसते ही इंफेक्शन फैलना शुरू कर देता है। इसके लक्षण एक दिन से लेकर 12 दिनों के भीतर दिखने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में ये मेनिनजाइटिस संक्रमण के समान होते हैं, जिसमें सिरदर्द, उल्टी और बुखार होते हैं। इसके बाद गर्दन में अकड़न, दौरे आने शुरू हो जाते हैं। यहां तक कि इस संक्रमण की वजह से कई लोग कोमा तक में जा सकते हैं। इसके लक्षण नजर आने के बाद एक इंसान औसतन पांच दिनों के अंदर मर जाता है।

ये बीमारी संक्रामक नहीं

यह बीमारी एक से दूसरे इंसान में नहीं फैलती। डॉ. अग्निहोत्री के अनुसार, 1965 में पहली बार इसकी पहचान हुई थी। तब से लेकर अब तक 56 सालों में दुनियाभर में 300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा करीब 150 मामले अमेरिका में आए हैं। इस बीमारी से संक्रमित 98 प्रतिशत लोग दम तोड़ देते हैं।

क्या है इलाज

इसका अभी तक कोई सटीक इलाज नहीं मिल पाया है। ऐसे में इस बीमारी से संक्रमित मरीज का इलाज बैक्टीरियल मेंनिनजाईटिस के जरिए किया जाता है। सतर्कता और बचाव ही इसके लिए सही इलाज है। ये ज्यादातर गर्म पानी वाली नदियों, झीलों, झरनों में मिलते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री वेस्ट वाले गंदे पानी, जमीन के अंदर के गर्म पानी, स्विमिंग पूल, नल के पानी में भी ये जीव मिलता है। इसलिए सभी को साफ पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। भले ही वह नहाने के लिए ही क्यों न कर रहे हों।

मस्तिष्क खाने वाले अमीबा कहाँ पा सकते हैं?

अनुपचारित, गर्म पानी मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के लिए आदर्श वातावरण है। यह नेगलेरिया के लिए एक आदर्श आवास है। यह गर्म पानी में 115 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर बिना मरे जीवित रह सकता है। निम्नलिखित कुछ स्थान हैं जहां वे पाए जाते हैं।

- गर्म तालाब, झीलें और चट्टानी संरचनाएँ
- कीचड़ के गड्ढे
- गर्म धाराओं वाली नदियाँ, विशेषकर कम जल स्तर वाली नदियाँ
- स्पा और स्विमिंग पूल जहां पानी का उपचार नहीं किया जाता है
- अनुपचारित नगरपालिका जल आपूर्ति या कुएँ का पानी
- गर्म झरनों सहित विभिन्न भूतापीय जल स्रोत
- तापीय रूप से दूषित पानी, जैसे कि बिजली संयंत्रों से एक्वैरियम अपवाह
- बच्चों के लिए जल क्रीड़ा क्षेत्र जलीय पार्क।

रायगढ़ में द केरला स्टोरी चरितार्थ होने पर बिफरे सांसद एवं भाजपा नेता

■ संयुक्त प्रेस वार्ता में सांसद गोमती, भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी ने पीड़िता हेतु एक करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति की मांग

रायगढ़। रायगढ़ सांसद गोमती साय भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने बुधवार को पंचायती धर्म शाला के आयोजित प्रेस वार्ता में लव जेहाद को लेकर रायगढ़ में भी केरला स्टोरी घटित होने का गंभीर आरोप लगाते हुए जारी संयुक्त बयान के कहा कि रायगढ़ की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। भाजपा ने इस मामले पर कार्यवाही को लेकर पुलिस प्रशासन पर शिथिलता का आरोप भी लगाया।

सांसद गोमती ने कहा द केरला स्टोरी में दिखाया गया सच रायगढ़ में भी चरितार्थ हुआ। प्रेस वार्ता के दौरान पीड़िता का भाई एवम पिता भी मौजूद रहे।पीड़ित परिवार ने भी पुलिस की कार्यवाही पर असंतोष जताते हुए कठोर कार्यवाही की मांग की।प्रदेश भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा समाज विशेष के दानिश खान ने महिला का गर्भपात कराया,इसके पहले युवती से हुई बच्ची भी गायब है ।पीड़ित परिवार भी पुलिस कार्यवाही से असंतुष्ट है ।ओपी चौधरी ने कहा भूपेश सरकार की तुष्टिकरण की नीति की वजह से प्रदेश में लव जेहाद के मामले तेजी से बढ़े रहे है। केरला स्टोरी में दिखाया गया भयानक सच भी आज इस मामले में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री इस जिले के तीन दिवसीय प्रवास में है । इस घटना को लेकर उनके मुलाकात करने का जिक्र भी उन्होंने किया।

भाजपा नेताओं ने कहा प्रदेश का सामाजिक सौहार्द एवं सदभाव का माहौल बिगड़ रहा है। इस मामले में न्यायिक जांच कमेटी एस आई टी के गठन की मांग करते हुए प्रभावित परिवार को एक करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति के अलावा अभियुक्त पर लव जेहाद के मामले सहित हत्या,भ्रूण हत्या,बच्ची के अपहरण समेत प्रताड़ना का मामला दर्ज कर कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग भी की ।आगामी 48 घंटे के अंदर यदि प्रशासन ने कार्यवाही नही की तो भाजपा इस मुद्दे पर सड़क की लड़ाई लड़ेगी। इस दौरान जिला ध्यक्ष उमेश अग्रवाल वरिष्ठ भाजपा नेता गुरुपाल भल्ला पूर्व विधायक विजय अग्रवाल सभापति पूनम पटेल सोलंकी महिला आयोग की पूर्व सदस्य एवं पूर्व नपा अध्यक्ष शीला तिवारी महिला मोर्चा महामंत्री दुर्गा देवांगन सहित भाजपा से जुड़े नेता गण कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पीएम मोदी अगस्त में आएंगे छत्तीसगढ़

■ भिलाई आईआईटी का करेंगे लोकार्पण, फ्लाई ओवर और सोलर प्लांट भी करेंगे समर्पित

भिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। वह अगस्त के पहले सप्ताह में यहां पहुंचेंगे। इस दौरान भिलाई के कुटेलाभाठा में नव निर्मित आईआईटी का लोकार्पण करने के साथ ही फ्लाई ओवर और रेलवे के सोलर प्लांट को भी जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की सूचना आईआईटी प्रबंधन को भेज दी गई है। हालांकि अभी कार्यक्रम की जानकारी जानकारी नहीं दी गई है। करीब एक सप्ताह बाद इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। जिला प्रशासन की ओर से सोमवार से तैयारी शुरू कर दी जाएगी।

दो घंटे का हो सकता है कार्यक्रम

जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी हवाई मार्ग से सीधे कुटेलाभाठा भिलाई आईआईटी कैंपस पहुंचेंगे। इसके लिए कैंपस में ही चार हेलीपैड बनाये जाएंगे। वहां करीब दो घंटे रुकने का कार्यक्रम हो सकता है। इस दौरान वे लोकार्पण के बाद वहां के छात्रों से भी मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री के साथ प्रदेश

के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन भी होंगे। इससे पहले मई के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री के आने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अधूरे निर्माण कार्य के चलते लोकार्पण की तारीख में बदलाव किया गया है।

इन विकास कार्यों का भी करेंगे लोकार्पण

आईआईटी कैंपस से ही प्रधानमंत्री मोदी नेशनल हाइवे पर बने दो फ्लाई ओवर का भी लोकार्पण करेंगे। भिलाई के सुपेला और पावर हाउस में बन रहे ब्रिज का निमार्ण पूरा हो जाएगा। पावर हाउस में बना फ्लाई ओवर अनोखा है, जो पुराने ब्रिज के ऊपर से निर्माण किया जा रहा है। वहीं चरोदा में रेलवे की ओर से बनाए गए सोलर प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इस सोलर प्लांट के शुरू होने के बाद रेलवे को सालाना 360 करोड़ की बचत होगी। फिलहाल यह बनकर तैयार हो चुका है।

बिना तलाक के दूसरा विवाह अमान्य व अवैधानिक : डॉ. किरणमयी नायक

■ छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा जनसुनवाई संपन्न

कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य श्रीमती अर्चना उपाध्याय ने कलेक्टोरेट कार्यालय सभाकक्ष में महिला उत्पीडन से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जनसुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. नायक की अध्यक्षता में आज प्रदेश स्तर की 178वीं और कोरबा जिले में 5वीं जन सुनवाई संपन्न हुई।

सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि मृतक भाई ने अनावेदक पक्ष से उधार में कपड़ा लिया था जिसके बकाया राशि का अनावेदक गण अनावेदिका से पैसे मांग रहे है। अनावेदक ने बताया कि 15 से 20 साल पहले आवेदिका के भाई ने 385 रुपए नहीं दिया था, अनावेदक द्वारा बताया कि छोटी सी राशि की मांग नहीं किया गया है। ऐसे दशा में प्रकरण को चलाए जाने का कोई मतलब नहीं है इस हेतु प्रकरण को नस्ती बद्ध किया गया। जनसुनवाई के एक अन्य प्रकरण में दोनो पक्ष की बातों को सुना गया। एक-दूसरे के खिलाफ की गई शिकायतों को सुनने एवं दस्तावेजों को देखने में समय लगने के कारण दोनों पक्षों को समझाईश दिया गया। साथ ही दोनो पक्षों को अपने-अपने दस्तावेजों की तीन प्रति शपथपत्र तैयार करवा कर आयोग में जमा कराने के निर्देश दिए गए। आवेदिका के प्रकरण की अगली सुनवाई रायपुर में रखी जाएगी। अन्य प्रकरण में आवेदिका उपस्थित, अनावेदक 02 और 03 उपस्थित रहे एवं शेष अनावेदक अनुपस्थित थे। आवेदिका ने बताया कि उसके पति ने दूसरी महिला के साथ विवाह कर लिया है, जबकि आवेदिका से विधिवत् तलाक नहीं हुआ है। उनकी अनुपस्थिति होने पर थाना उरगा व थाना दीपका के तहत नौकरी व निवास है। दोनों थाना के माध्यम से अनावेदक को

उपस्थित कराने के लिए थाना प्रभारी द्वारा पत्र प्रेषित की जाए। आवेदिका अपने पति का ऑफिस व घर का पता लिखकर जमा करें। इस प्रकरण में दूसरी लड़की के माता-पिता एवं आवेदिका के सास-ससुर और पति का नाम दर्ज किया जाए एवं शेष अनावेदक गणों का नाम हटाया जाए। प्रकरण की अगली सुनवाई रायपुर में रखा जाएगा।

अन्य प्रकरण में आवेदिका अनुपस्थित, अनावेदकगण उपस्थित रहे। अनावेदक ने बताया कि उसके बेटे की मृत्यु 19 फरवरी 2023 में हुई है और अनावेदिका उस समय नहीं थी। केवल उसके अंतिम संस्कार में उपस्थित हुई। अनावेदक ने पहले ही घर को अपने बेटे के नाम पर कर दिया था जो कि मकान अनावेदिका ने अपने खुद की कमाई से बनाया था। वर्तमान में वह अपनी बेटी के साथ नागपुर में रहती है, स्वास्थ्य खराब होने से बार-बार सुनवाई में आने में असमर्थ है। वह केवल अपने पोते उम्र 14 वर्ष से कभी कभी मिलना चाहती है। उसे आवेदिका के सम्पत्ति में कोई रूची नहीं है। आवेदिका को टेलीफोन से सूचना दिए जाने पर सुनवाई में आने से मना कर दिया गया है। इस प्रकरण की आगामी सुनवाई रायपुर में नियत किया जाता है। 14 जून 2023 को रायपुर में सुनवाई हेतु प्रस्तावित है। अन्य प्रकरण में आवेदिका उपस्थित, अनावेदक अनुपस्थित रहा। आवेदिका ने बताया कि अनावेदक ने उसका शारिरीक एवं आर्थिक शोषण किया है, उसे धमकाने घर में भी आता है। उसकी शिकायत पुलिस में की गई है।

पुरेनाखार के भू-विस्थापितों ने चार सूत्री मांग रखी

एनटीपीसी के राखड़ बांध के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

कोरबा। ग्राम पंचायत लोतलोता चारपारा व पुरेनाखार के भू-विस्थापितों ने ग्रामीणों ने एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा किए जा रहे वादा खिलाफी को लेकर गोरेलाल यादव अध्यक्ष ब्लाक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण कटघोरा व डा शेख इश्तियाक विधायक प्रतिनिधि की अगुवाई में धनरास राखड़ बांध कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही चार सूत्री मांग रखी।

ग्राम पंचायत लोतलोता पुरेनाखार और चारपारा के ग्रामीणों ने पिछले वर्ष प्रदर्शन किया था और छह सूत्रीय मांग पत्र रखा था। एनटीपीसी प्रबंधन व ग्रामीणों के बीच सहमति के साथ पूरा करने का आश्वासन दिया था। इसमें राखड बांध से उड रहे राख से ग्रामीणों के जीवन पर दुष्प्रभाव व क्षतिपूर्ति राशि देनेए 30 बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने, आईबीपी से पुरेनाखार तक पूरी तरह खराब हो चुकी सडक को नए सिरे से बनाने, जर्जर हो चुके स्कूल भवन मरम्मत और राखड बांध में पानी का छिडकाव कर गीला रखने की सहमति बनी थी, परंतु एक वर्ष बीत जाने के बाद एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा कोई अमल नहीं की गई। इससे क्षुब्ध हो कर क्षेत्र के भू-विस्थापितों ने धरना प्रदर्शन कर एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी की। जानकारी मिलने पर एनटीपीसी के अधिकारी स्थल पर पहुंचें और आंदोलनकारियो से चर्चा कर पांच दिनों में सभी मांग पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ।

इस दौरान ब्लाक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष यादव ने बताया कि क्षेत्र के भू-विस्थापित राखड से काफी परेशान है। चारों ओर राखड के प्रदूषण फैलने से लोगों के जन जीवन प्रभावित हो रहा है। लोतलोता के 22 किसानों के उपजाऊ निस्तारी भूमि को राखड बांध के लिए एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहण किया गया है। इससे लोतलोता क्षेत्र राखड बांध से पूरी तरह प्रभावित है। डा शेख इश्तियाक ने कहा कि पांच दिनों में ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं हुई तो फिर से एनटीपीसी के खिलाफ क्षेत्रीय विधायक की अगुवाई में आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान विकास सिंह जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस, राहुल शर्मा युवा विधानसभा उपाध्यक्ष, ज्ञानेश्वरी देवी सरंपच, लक्ष्मी कंवर प्रदेश महासचिव, छबि लाल, सूर्यभवन दास, अजय चौहान, रति राम और बैशाखू राम यादव समेत काफी संख्या महिलाएं उपस्थित रही।

कार्रवाही नहीं होने से रेत माफियाओ के हौसले बुलंद

कोरबा। रेत माफ्यिाओ ने न केवल नदी नालों पर कब्जा किया हुआ है । बल्कि जिस मार्ग में भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है । वैसे सड़को को भारी वाहनों को परिचालन करवा कर सड़क की स्थिति को बद से बत्तर कर दिया है । जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम से की है ।

बता दे कि बीते कुछ महीनों से रेत माफ्यिाओ का दबदबा पोड़ी उपरोड़ा क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। रेत माफ्यिा ऐसे नदी नालों से अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर रहे है । इसमें ग्रामीणों का निस्तारी हो रहा है रेत उत्खनन किये जाने से जंहा ग्रामीणों की निस्तारी में परेशानी हो रही है । वही मशीनों से अवैध रेत उत्खनन किये जाने से ग्रामीणों के जान माल को भी खतरा है । इस बात को लेकर ग्रामीणों ने स्थानीय स्तर पर शिकायत भी दर्ज कराई गई थी । पर स्थानीय स्तर पर कार्यवाही नही होने से रेत माफ्यिाओ के हौसले बुलंद हो गए है ।

ग्रामीणों ने बताया कि उनके द्वारा किये गए शिकायत की जानकारी होने पर रेत माफ्यिो के गुर्गे ग्रामीणों को धमकिया भी दे रहे है । जिससे ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है अब ग्रामीण इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर इनकी दहशत से किस तरह छुटकारा मिल पायेगा। बताया जा रहा है कि रेत माफ्यिाओ का दबदबा इस कदर हावी है कि अधिकारी भी उनके खिलाफ कार्यवाही करने से गुरेज कर रहे है । बीते दिनों रेत मकफ्यिो की गाड़ियां रेत का अवैध उत्खनन कर रही थी तब इसकी जानकारी जनपद सदस्य भोला गोस्वामी यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष को होने पर उसका विरोध करने गए थे । जिससे हुज्जत बाजी करने से भी रेत माफ़्यिा ने गुरेज नही किया। तब इस मामले की शिकायत एसडीएस व बांगो थाना प्रभारी से की गई थी जिसपर कार्यवाही करते हुए रेत उत्खनन में लगाई गई मशीन व हाइवा वाहनो की जप्त किया गया था। लेकिन रेत माफ्यिा का गिरोह अभी भी सक्रिय है । ग्रामीणों ने इस मामले में एसडीएम से शिकायत की है ।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

छत्तीसगढ़ में विकास का भगीरथ गंगा : अश्वनी साहू

पाटन। दुर्ग कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष अश्वनी साहू ने वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार के संदर्भ में कहा की शास्त्रों की मान्यता अनुसार जब कोई व्यक्ति मुश्किल कार्य को आसान कर देता है ।उसी प्रकार वर्तमान परिवेश में छत्तीसगढ़ सरकार का सफल नेतृत्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों में है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वन गमन पथ का निर्माण कर एवं कौशल्या महोत्सव की शुरुआत की है। गोबर से बने उत्पाद की देश ही नहीं विदेशों में चर्चा हैं। गोमूत्र की खरीदी वर्मी कंपोस्ट बनाना बनाने की चर्चा पूरे देश मे है ।विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया प्रसिद्ध कथाकार प्रदीप मिश्रा शंकराचार्य, अवि मुक्तेश्वरानंद ने छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओ की तारीफ़ कर चुके है। वह इस बात का प्रमाण है कि भूपेश बघेल की सरकार ने राम राज्य की कल्पना को मूर्त रूप दे रहे है छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रायगढ़ में तीन दिवसीय अन्तराष्ट्रीय रामायण मेला का शुभारंभ कर दिये है ।जिसकी बानगी देखने को मिल रही हैं।

नगरीय निकाय उप निर्वाचन नाम निर्देशन पत्र जमा होंगे

दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के आदेशानुसार नगरीय निकाय उप निर्वाचन के तहत दुर्ग जिले के नगर पालिक निगम दुर्ग के वार्ड क्रमांक 42 कसारीडीह पश्चिम तथा नगर पालिका परिषद अहिवारा के वार्ड क्रमांक 14 अम्बेडकर नगर के रिक्त पार्षद पद के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 02 जून 2023, शुक्रवार को पूर्वान्ह 10.30 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया गया। प्रकाशन के तत्काल बाद रिटर्निंग ऑफिसर अथवा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 9 जून 2023 अपरान्ह 3 बजे तक है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 10 जून दिन शनिवार प्रात: 10.30 बजे से किया जाएगा। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 12 जून दिन सोमवार अपरान्ह 3 बजे तक है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन 12 जून को अभ्यर्थिता वापसी के बाद की जाएगी।

शिवकुमार ने एनटीपीसी नवा रायपुर का कार्यभार संभाला

कोरबा। सी. शिवकुमार ने 1 जून गुरुवार को एनटीपीसी नवा रायपुर का कार्यभार क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक पश्चिमी क्षेत्र. और यूएसएससी के रूप में संभाला। इससे पहले वे एनटीपीसी नवा रायपुर में यूएसएससी यूनिफाइड शेयर्ड सर्विसेज सेंटर के रूप में कार्यरत थे। कार्यकारी निदेशक शिवकुमार ने श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद वर्ष 1985 में एनटीपीसी के साथ ईटी के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। एनटीपीसी के साथ उनका 38 से अधिक वर्षों का अनुभव है। अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने एनटीपीसी के विंध्याचल, कोरबा, मौदा, बीआरबीसीएल नबीनगर दादरी और सीसी.ईओसी नोएडा में काम किया। उन्होंने एनटीपीसी के बीआरबीसीएल और दादरी स्टेशनों का भी नेतृत्व किया। उनके पास यांत्रिक निर्माण और रखरखाव, परियोजना निर्माण, सुरक्षा और यूनिफाइड शेयर्ड सर्विसेज के क्षेत्रों में समृद्ध और विविध अनुभव है। आने वाले दिनों में उनके मार्गदर्शन और गतिशील नेतृत्व का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा।

घर के बाहर खड़ी कार में लगाई आग

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बदमाशों ने गुरुवार देर रात घर के बाहर खड़ी एक कार में आग लगा दी। इसके चलते कार धू-धू कर जल गई। आग लगी देख आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। हालांकि दमकल के पहुंचने से पहले ही लोगों ने आग पर काबू पा लिया। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई है। आग लगाने वालों के बारे में पता नहीं चल सका है। कार मालिक का कहना है कि किसी जानकार का ही हाथ है। करीब 15 दिन पहले भी उसकी कार में तोडफोड़ की गई थी। मामला कोतवाली क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, रामसागर पारा निवासी विकास फ्रांसिस गुरुवार रात काम से लौटा और कार घर के बाहर खड़ी कर दी। क्षेत्र में लाइट नहीं होने के कारण वह रात करीब 1.30 बजे तक बाहर ही टहलता रहा। रात करीब 2.30 बजे पड़ोसियों ने उसे कार में आग लगी होने की जानकारी दी। वह दौड़कर बाहर आया तो धू-धू कर कार जल रही है। फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन उसके आने से पहले ही स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया।

दंतेवाड़ा के तीन शिक्षकों का दल चढ़ा एवरेस्ट बेस कैंप

दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के तीन शिक्षकों की टीम ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप की ऊंचाई 5364 मीटर चढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। बेस कैंप तक पहुंचने वाली दंतेवाड़ा जिले की यह पहली टीम है। इस टीम में कमल किशोरक्त देवेद्र सोनी व सुजीत सिंह चौहान है। दंतेवाड़ा लौटने के बाद शिक्षकों ने बताया कि पिछले दो वर्षों से एवरेस्ट के बेस कैंप ट्रैक की तैयारी करते हुए ट्रैकिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया। शिक्षक कमल किशोर, सुजीत चौहान, देवेन्द्र ने बताया माउंट एवरेस्ट को किताबों में पढने, वीडियो और फोटो देखना अलग बात है, लेकिन यहां तक पहुंचने वाला अनुभव बहुत ही रोमांचकारी है। यह कठिन था लेकिन हम सभी ने शिखर पर पहुंचने के लिए दृढ़ निश्चय किया था कि किसी दिन, हम सभी एवरेस्ट फतह करेंगे। उबड़-खाबड़ और ठंडे इलाकों से गुजरते हुए ट्रैक को आठ दिनों में पूरा किया। उन्होंने बताया कि तेनजिंग हिलेरी लूकला एयरपोर्ट पर लैंड करते ही सफर का रोमांच शुरू हो जाता है, जो एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने तक जारी रहता है।

बण्डापाल में आजादी के 75 साल बाद पहली बार पहुंचा प्रशासन

■ नक्सल प्रभावित ग्रामीणों की सुनी परेशानियां

कांकेर। कांकेर जिला बस्तर संभाग का सबसे बड़ा जिला है। नक्सल प्रभावित इस जिले के कुछ इलाके ऐसे हैं। जिनमें नक्सलियों की काफी पैठ है। उन्ही में से एक है बण्डापाल। जिले के अंतिम छोर में बसे इस धुर नक्सल प्रभावित गांव में ऐसा पहली बार हुआ। जब आजादी के बाद प्रशासन उन तक खुद चल कर पहुंचा। नक्सलियों की दहशत इतनी है विकास के कार्यो को गति देना अंदरूनी इलाकों में प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं।

अब तक जहां कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंच सका। वहां एक महिला कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला अपनी पूरी प्रशासनिक टीम के साथ

वहां पहुंच कर ग्रामीणों से रूबरू हुए। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला अपने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ पहुंची। शिविर में लगभग 4 से अधिक गांव के ग्रामीण एकत्रित हुए। जिनसे प्राप्त हुए 136 आवेदन में 13 का तत्काल मौके पर निराकरण भी किया गया। ग्रामीणों की मांग और जरूरतों के अनुरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण, बोरखनन, पीडीएस गोदाम सहित अन्य कार्यो के लिए लाखों रुपये की स्वीकृति भी त्वरित रूप से प्रदान की गई। जिससे ग्रामीण बेहद खुश नजर आए। ग्राम बण्डापाल घोर नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण ग्रामीणों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। आज तक जहां कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंच पाया था। वहां माह दिसम्बर 2022 के अंत में एक महिला कलेक्टर ने ग्रामीणों के बीच पहुंच ना केवल उनकी समस्या सुनी थी। बल्कि उसे दूर करते हुए दुबारा जल्द आने का भरोसा दिया था। जिसे आज पूरा करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कर योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया है।

कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कहा कि मेरे साल भर के कार्यकाल का यह सबसे अविस्मरणीय क्षण है, इसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैं कभी इस गांव में आई थी। कांकेर जिले के सबसे अच्छे डॉक्टर यहां मौजूद हैं, सभी लोग अपना स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य करायें।

इस अवसर पर जल जीवन मिशन, कृषि और जनपद कार्यालय द्वारा स्टॉल लगाया गया था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाकर मरीजों का उपचार किया गया। साइकिल का वितरण किया गया। ग्रामीणों की मांग के अनुरूप विभिन्न घोषणाएं भी की गई। साथ उन्हें वे तमाम सुविधाएं मुहैय्या कराने का भरोसा दिया। जिनकी उन्हें आवश्यकता है। ग्रामीण प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अपने बीच पाकर बेहद खुश नजर आए। ग्रामीण भी प्रशासन को अपने नजदीक पाकर बेहद खुश नजर आए। प्रशासन अगर इसी तरह के कार्य करता रहा तो वो भी दिन दूर नहीं कि नक्सल पर प्रभावित क्षेत्र के लोग सुविधाओं से महरूम रह सकेंगे।

76 करदाताओं का चेक हुआ बाउंस

■ 27 पहुंचे कैश लेकर, 49 को मिला 3 दिन का समय

भिलाई नगर। नगर निगम भिलाई क्षेत्र के 76 करदाताओं ने टैक्स जमा करने के रुप में चेक से पेमेंट किया था लेकिन उनका चेक बाउंउ हो गया। निगम ने सभी को नोटिस जारी किया और 27 लोग कैश के रुप में टैक्स जमा किया, लेकिन 49 करदाताओं ने अभी तक टैक्स जमा नहीं किया, उन्हें अब 3 दिन का और मौका दिया है, अगर इस दौरान भी वे टैक्स जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया जाएगा।

भिलाई निगम में टैक्स जमा करने के लिए 76 करदाताओं ने चेक का उपयोग किया, परंतु खाता में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने के चलते निगम के

खाते में इस राशि का आहरण नहीं किया जा सका। ऐसे सभी करदाताओं को निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर नोटिस जारी किया गया था। इनमें से 27 लोगों ने निगम कार्यालय पहुंचकर कैश में टैक्स जमा लेकिन 49 लोगों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं किया हैं, उन्हें 3 दिन का और मौका दिया है इसके बाद सोमवार को इनके खिलाफ एफआईआर की रिपोर्ट दर्ज करवाया जाएगा। जारी सूची के मुताबिक सुनीता यादव, जय शेखरन, अनिल कुमार, संजीव विश्वकर्मा, श्यामाचरण पांडे, सुनीता यादव, ममता निर्मलकर, पवन कुमार चौधरी, खजाना सिंह, गणेश लाल दास गुप्ता, गायत्री सिंह, फत्तू, भावना जैन, अशोक कुमार गुप्ता, सोमनाथ गुप्ता, रविंद्र सिंह कुशवाहा, आशा यादव कौशल, भावना जैन, वेंकटेश्वरलू, रवेंद्र सिंह कुशवाहा, राजेश अग्रवाल, मुरलीधर, रमजान खान, कामिनी वर्मा, ठाकुर सिंह, रविंद्र सिंह कुशवाहा, अशोक अग्रवाल, तेजू बाई जैन एवं मेघा जैन, आशा देवी, अजय चौहान, मंजीत सिंह बग्गा, वीरेंद्र कुमार वर्मा, मंजू जयसवाल, सर्बिजत सिंह, मंजू जयसवाल, हिंसा राम वर्मा, अलका नंदा, शेखलाल अशरफी, सरोज साहनी, उपकार सिंह, कमलादेवी गणेशनी, पैवहरी शरण सिंघानी, नवल दास मानिकपुरी, श्यामलाल, नजमा खातून, सुमा पाल के द्वारा राशि निगम कोष में जमा नहीं की गई है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

भाजपा ने की पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के सभी दलों ने विभिन्न जिलों में पंचायत चुनाव के के बीच 11 लोगों की हत्या की शनिवार को निंदा की जबकि विपक्षी भाजपा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। वहीं, चुनावी हिंसा में अपने छह समर्थकों को खोने वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने विपक्ष पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और मतदाताओं की सुरक्षा करने में विफल रहने के लिए केंद्रीय बलों की आलोचना की। दूसरी ओर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को खुली छूट मिल रही है और जनादेश को लूटा गया है। वहीं, माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने दावा किया कि केंद्रीय बल को सही तरीके से मॉबिलाइज नहीं किया गया। आधी रात से मारे गए लोगों में तृणमूल कांग्रेस के छह सदस्य, भाजपा, माकपा, कांग्रेस और आईएसएफ के एक-एक कार्यकर्ता और एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं जिनकी राजनीतिक पहचान का पता नहीं चल सका है। राज्य के वरिष्ठ मंत्री शशि पांजा ने कहा, कल रात से चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं।

यूसीसी लागू करना इतना आसान नहीं : आजाद

श्रीनगर। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर जबरदस्त चर्चा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर बयान दिया है, तब से इसकी चर्चा ने और भी जोर पकड़ लिया है। इन सबके बीच डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने बड़ा बयान दिया है। गुलाम नबी आजाद ने साफ तौर पर कहा है देश में समान नागरिक संहिता को लागू करना इतना आसान नहीं रहेगा जितना कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना आसान रहा। उन्होंने दावा किया कि इसका सभी धर्म पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जितना आसान नहीं है। इसमें सभी धर्म हैं, केवल मुस्लिम ही नहीं, बल्कि इसमें सिख, ईसाई, आदिवासी, जैन और पारसी भी हैं। आजाद ने कहा कि एक ही समय में इतने सारे धर्मों को नाराज करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा।

जहरीली शराब वाले मामले पर नीतीश कुमार का यू टर्न

पटना। इस वर्ष अप्रैल में पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया, पहाड़पुर, हरसिद्धि और सुगौली में जहरीली शराब पीने से 41 लोगों की मौत हुई थी। इन मौत होने का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीली शराब से मौत की पुष्टि हुई थी। बिहार पुलिस के मुताबिक अब सरकार ने बैकफुट पर आने का फैसला किया है और शराब पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। सरकार अब जहरीली शराब से हुई मौतों के पीड़ितों के परिजनों के लिए 2.1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था कर रही है। इस संबंध में सब तैयारी हो चुकी है और जल्द ही पीड़ितों के परिजनों को ये राशि सौंपी जाएगी। इस संबंध में जदयू के राष्ट्रिय महासचिव राजीव रंजन ने भी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अन्य जिलों में भी जहरीली शराब से पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा दिए जाने की तैयारी की जा रही है।

शिंदे के 40 और ठाकरे गुट के 14 विधायक को नोटिस जारी

मुंबई। महाराष्ट्र में जारी सियासी उटापटक के बीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर अब एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर जवाब मांगा है। विधायकों को जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। यह घटनाक्रम विधानसभा अध्यक्ष नारवेकर को चुनाव आयोग से शिवसेना के संविधान की एक प्रति मिलने के एक दिन बाद आया है, जिसमें यह जानकारी दी गई थी कि सीएम शिंदे सहित 16 शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई जल्द ही शुरू होगी। 11 मई को शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अदालत ने कहा कि वह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए गठबंधन सरकार को बहाल नहीं कर सकती, क्योंकि शिवसेना नेता ने शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना इस्तीफा देने का फैसला किया।

राजस्थान चुनाव में 'सामूहिक नेतृत्व' ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता: पायलट

नयी दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने राजस्थान विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ने का शनिवार को स्पष्ट संकेत दिया और कहा कि सामूहिक नेतृत्व ही चुनाव में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। पायलट ने साक्षात्कार में यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उनसे कहा है कि 'भूलो, माफ करो और आगे बढ़ो' तथा खरगे की यह बात उनके लिए एक सुझाव होने के साथ ही पार्टी अध्यक्ष का निर्देश भी है। गहलोत के साथ मतभेदों को खत्म कर आगे बढ़ने का स्पष्ट संकेत देते हुए पायलट ने कहा, ''अशोक गहलोत उम्र में मुझसे बड़े हैं। उनको ज्यादा अनुभव है। उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, तो मैंने कोशिश की थी कि सबको साथ लेकर चलूं। मुझे लगता है कि आज वह मुख्यमंत्री हैं, तो यह कोशिश कर रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलें।'

बीआरएस और कांग्रेस तेलंगाना के लिए खतरनाक

तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने 6100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत की

वारंगल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तेलंगाना दौरे के दौरान भाजपा के एक विशाल जमसभा को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने केंद्र की के चंद्रशेखर राव की सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में वर्तमान सरकार ने 4 काम किए हैं, पीएम मोदी और बीजेपी सरकार को गाली देना, उन्होंने एक परिवार को सत्ता का केंद्र बनाया, उन्होंने तेलंगाना के आर्थिक विकास को उथल-पुथल में धकेल दिया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि केसीआर ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबा दिया, तेलंगाना में ऐसी कोई परियोजना नहीं है जो न हो भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केसीआर सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है।

केसीआर सरकार यानि सबसे भ्रष्ट सरकार

मोदी ने कहा कि वारंगल की धरती जनसंघ के समय से ही हमारी विचारधारा का मजबूत किला रही है। आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में खड़ी है और इसे साकार करने में तेलंगाना के लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि केसीआर सरकार यानि सबसे भ्रष्ट सरकार। बल्कि अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं। उन्होंने कहा कि हम पहले दो राज्यों या दो देशों की सरकारों के बीच विकास से जुड़े समझौतों की खबरें सुनते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ है, जब दो राजनीतिक दलों और दो राज्य सरकारों के बीच भ्रष्टाचार की डील के आरोप लगे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन सभी वंशवादी पार्टियों की नींव भ्रष्टाचार में है, वंशवादी कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को पूरे देश ने देखा है, और पूरे तेलंगाना में बीआरएस द्वारा राज्य में भ्रष्टाचार का स्तर देखा गया है... बीआरएस और कांग्रेस दोनों ही तेलंगाना के लोग के लिए खतरनाक हैं।

तेलंगाना में भ्रष्टाचार का खुला खेल

प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना में भ्रष्टाचार का जो खुला खेल चल रहा है, इसका सबसे बड़ा नुकसान, यहां के युवाओं को उठाना पड़ा है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्कैम के बारे में कौन नहीं जानता? यहां की सरकार ने सरकारी नौकरियों को अपने नेताओं की तिजोरी भरने का माध्यम बना लिया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि आजकल कुछ लोग चुनाव से

पहले, जनता को गुमराह करने के लिए झूठी गारंटी लेकर आ रहे हैं। लेकिन भाजपा चुनाव जीतने के लिए झूठी बातें या झूठे गारंटी कार्ड नहीं बांटती।

नागपुर-विजयवाड़ा कॉरिडोर के प्रमुख खंडों सहित कई परियोजनाओं की आधारशिला रखने और कई अन्य विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद पीएम मोदी ने वारंगल में एक रैली को संबोधित किया। पीएम ने लगभग 6,100 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी केसीआर सरकार पर जमकर बरसे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज जब पूरी दुनिया भारत में निवेश के लिए आ रही है, विकसित भारत को लेकर इतना उत्साह है, तब तेलंगाना के सामने अवसर ही अवसर हैं। बीते 9 वर्षों में पूरी दुनिया में देश का गौरव बढ़ा है, भारत को लेकर आकर्षण बढ़ा है। इसका भी फायदा तेलंगाना को हुआ है। यहां पहले के मुकाबले अब ज्यादा निवेश आ रहा है और इसका फायदा तेलंगाना के युवाओं को हो रहा है, उन्हें नौकरी मिल रही है। हम पहले दो राज्यों या दो देशों की सरकारों के बीच विकास से जुड़े समझौतों की खबरें सुनते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ है, जब दो राजनीतिक दलों और दो राज्य सरकारों के बीच भ्रष्टाचार की डील के आरोप लगे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का भारत नया भारत है। बहुत सारी एनर्जी से भरा हुआ है। 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में हमारे पास एक गोल्डन पीरियड आया है। हमें इस मौके के हर पल का पूरा इस्तेमाल करना है। देश का कोई भी कोना तेज विकास की संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए। इन्हीं संभावनाओं को गति देने के लिए पिछले 9 साल में भारत सरकार ने तेलंगाना के विकास और कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया है। इसी कड़ी में आज तेलंगाना के कनेक्टिविटी और उत्पादन से जुड़े हुए 6 हजार करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। बता दें कि सुबह तेलंगाना के वारंगल पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने भद्रकाली मंदिर में पूजा-अर्चना की।

प्रधानमंत्री ऐलान करें कि भाजपा परिवार द्वारा संचालित पार्टी के साथ नहीं करेगी गठबंधन : कांग्रेस

नईदिल्ली। कांग्रेस ने शनिवार को वंशवाद की राजनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार हमलों का जवाब देते हुए उन्हें यह घोषणा करने की चुनौती दी कि भाजपा किसी भी ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी जिसे वह परिवार द्वारा संचालित मानती है। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार सेल के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री को राजनीति में परिवारों और वंशवाद के बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए, उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक परिवारों के लोगों से भरी हुई है। प्रधानमंत्री अगले लोकसभा चुनाव से पहले सामने आएं और घोषणा करें कि भाजपा किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, जो उनके अनुसार एक परिवार संचालित पार्टी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि साहस दिखाने दो...आत्मविश्वास दिखाने दो। आज उनके पास (लोकसभा में) 303 सीटें हैं। उन्हें यह घोषणा करने से कौन रोकता है कि, एक नीति के रूप में, भाजपा एक परिवार द्वारा संचालित पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी? उसे एक उदाहरण स्थापित करने दीजिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ज्ञानी को ज्ञानी मिलते हैं, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ठग मिल रहे हैं। वो ठगों के चुंबक हैं। ठग उनके आस-पास रहते हैं, उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, अपने विजिटिंग कार्ड्स में उनके कार्यालयों का नाम लगा देते हैं।

मैं थका नहीं हूं, मैं रिटायर नहीं हूं, मैं आग हूं : शरद पवार

उम्र पर अजित के तंज पर भड़के एनसीपी प्रमुख

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार के इस सुझाव का मजाक उड़ाया है कि उन्हें सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह काम करना जारी रखेंगे क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि वह काम करते रहें। अजित की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा, क्या आप जानते हैं कि मोरारजी देसाई किस उम्र में प्रधानमंत्री बने थे? मैं प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बनना चाहता, बल्कि लोगों की सेवा करना चाहता हूं। अजित पवार ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि 83 साल की उम्र में उनके चाचा के रिटायर होने का समय आ गया है।

यह दावा करते हुए कि वह अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, शरद पवार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को दोहराते हुए कहा, ना थके हुए हैं, न सेवानिवृत्त हुए हैं। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में पवार ने कहा, वे मुझे रिटायर होने के लिए कहने वाले कौन होते हैं? मैं अभी भी काम कर सकता हूं। न टायर्ड हूं, न रिटायर्ड हूं, मैं फायर हूं।

अजित पवार की उस टिप्पणी के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें दरकिनार कर दिया गया क्योंकि वह किसी के (शरद पवार के) बेटे नहीं थे, परिवार में उत्तराधिकार की लड़ाई पर इस सवाल के जवाब में अनुभवी राजनेता ने कहा, मैं इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं परिवार के बाहर पारिवारिक मुद्दों पर चर्चा करना पसंद नहीं करता।

पवार ने कहा कि अजित को मंत्री बनाया गया और उपमुख्यमंत्री भी बनाया गया, लेकिन उनकी बेटी सुप्रिया सुले को कोई मंत्री पद नहीं दिया गया, जबकि यह संभव हो सकता था। उन्होंने कहा कि जब भी एनसीपी को केंद्र में मंत्री पद मिला, वह दूसरों को दिया गया, लेकिन सांसद होने के बावजूद सुप्रिया को नहीं मिला।

पवार ने छगन भुजबल के इलाके में की रैली

अजित और आठ अन्य एनसीपी विधायकों के महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में शामिल होने के एक सप्ताह बाद शरद पवार शनिवार को नासिक जिले के येओला (ङ्घद्गश्चद्यड्ड) में एक रैली करके अपने राज्यव्यापी दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। यह बागी पार्टी नेता और मंत्री छगन भुजबल का निर्वाचन क्षेत्र है। अपनी पार्टी के पुनर्निर्माण की कवायद शुरू करने के लिए मुंबई से 250 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक छोटे से शहर येओला को पवार द्वारा चुना जाना, पार्टी के पुनर्निर्माण के लिए 80 वर्षीय नेता के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

प्रफुल्ल पटेल के आरोपों पर दिया यह जवाब

प्रफुल्ल पटेल के इन आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कि उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सारी शक्तियां दे दी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते थे कि सुप्रिया सुले राजनीति में आएं, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हमने प्रफुल्ल पटेल को 10 साल के लिए केंद्रीय मंत्री पद दिया। वह लोकसभा चुनाव हार गए, उसके बाद भी हमने उन्हें राज्यसभा की सीट दी।

खेल
प्रमुख समाचार

श्रीलंका और नीदरलैंड के बीच मुकाबला आज

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर 2023 का फाइनल मुकाबला कल (9 जुलाई) खेला जाएगा। श्रीलंका के सामने नीदरलैंड की टीम है। श्रीलंका पहले ही विश्व कप में अपनी जगह सुरक्षित कर चुका है।

दो बार का चैंपियन वेस्टइंडीज पहली बार भारत में अक्टूबर-नवंबर में होने वाली इस प्रतियोगिता में नहीं खेलेगा। श्रीलंका ने इस तरह से सुपर सिक्स में अपने पांचों मैच जीते। वह रविवार को होने वाले फाइनल में विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली दूसरी टीम नीदरलैंड से भिड़ेगा। सुपर सिक्स चरण के अपने 5 मैचों में 3 जीत और 2 हार के साथ नीदरलैंड आईसीसी क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर 2023 सुपर सिक्स अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। टीम के 6 अंक हैं। विक्रमजीत सिंह 87 की स्ट्राइक रेट से 313 रन के साथ नीदरलैंड के लिए शीर्ष रन-स्कोरर हैं। उन्होंने 3 छक्के और 35 चौके लगाए हैं।

स्कॉट एडवर्ड्स ने भी 113 की स्ट्राइक रेट से 313 रन बनाए हैं। बास डी लीडे नीदरलैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं और उन्होंने 22 की औसत और 5.66 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी करते हुए 15 विकेट लिए हैं।

श्रीलंका- दासुन शनाका (कप्तान), कुसल मेंडिस, पथुम निसांका, दिमुथ करुणारत्ने, चैरिथ असलांका, धनंजय डी सिल्वा, दुशान हेमंथा, वानिंदु हसरंगा, सदीरा समरविक्रमा, चमिका करुणारत्ने, लाहिरू कुमारा, दुष्मंथा चमीरा, कासुन राजिथा, महीश थिकशाना, मथीशा पथिराना।

नीदरलैंड- स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान), मैक्स ओ%डॉड, विक्रमजीत सिंह, माइकल लेविट, वेस्ले बर्रेसी, बास डी लीडे, नूह क्रॉस, तेजा निदामानुरु, शारिज़ अहमद, साकिब जुल्फिकार, लोगान वैन बीक, आर्यन दत्त, क्लेटन फ्लॉयड, रयान क्लेन , विवियन किंग्मा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

12 जुलाई को खुलेगा उत्कर्ष एसएफबी का आईपीओ

नईदिल्ली। वाराणसी की स्मॉल फाइनैंस बैंक (एसएफबी) उत्कर्ष स्मॉल फाइनैंस बैंक का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) का सब्सक्रिप्शन अगले हफ्ते खुलने वाला है। 500 करोड़ रुपये का यह आईपीओ बुधवार यानी 12 जुलाई को खुलेगा और 14 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। एंकर निवेशकों के लिए यह 11 जुलाई को खुलेगा। 12 से 14 जुलाई के बीच यह इश्यू खुलने वाला है। आईपीओ की सफलता के बाद 19 जुलाई को शेयरों का एलॉटमेंट (आवंटन) किया जाएगा। एलॉटमेंट पूरा होने के बाद गुरुवार यानी 20 जुलाई को शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में शेयरों को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बाद सोमवार, 24 जुलाई को स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसई और एनएसई) पर शेयरों की एंट्री हो जाएगी और ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी।

सुजलॉन एनर्जी जुटाएगी 2,000 करोड़ रुपये का फंड

नईदिल्ली। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि उसके बोर्ड ने कंपनी के धन जुटाने की योजना को हरी झंडी दे दी है। कंपनी के बोर्ड ने 2,000 करोड़ रुपये तक धन जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। शेयर बाजार को दी गई सूचना के मुताबिक, कंपनी रकम जुटाने के लिए विभिन्न वित्तीय रास्ते तलाशेगी। बोर्ड ने 'इतनी संख्या में पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर और/या परिवर्तनीय बॉन्ड और/या गैर-परिवर्तनीय ऋण उपकरण और/या किसी भी अन्य उपकरण और/या उपकरणों के संयोजन को डिटैचेबल वारंट के साथ या बिना अधिकार के साथ जारी करने को मंजूरी दे दी है।' सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, वारंट धारकों को इक्विटी शेयरों को परिवर्तित करने या सदस्यता लेने के लिए या अन्य किसी रूप से इस्तेमाल करने का अधिकार होगा।

लोकल करेंसी से भारत और तंजानिया के बीच बढ़ेगा व्यापार

नईदिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत और तंजानिया ने स्थानीय करेंसी (लोकल करेंसी) में व्यापारिक सौदों का निपटान शुरू कर दिया है जिससे दोनों देशों के बीच कमर्शियल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। तंजानिया के दौरे पर पहुंचे जयशंकर ने यहां उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इस अफ्रीकी देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है और वित्त वर्ष 2022-23 में यह 6.4 अरब डॉलर रहा पर पहुंच गया था। जयशंकर ने कहा, 'इस बात को ध्यान में रखें कि यह न केवल बहुत अच्छा द्विपक्षीय व्यापार है बल्कि यह द्विपक्षीय व्यापार संतुलित भी होता जा रहा है। आपसी व्यापार में कई नए उत्पादों को जोड़ा जा रहा है। भारत तंजानिया से होने वाले निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य बना हुआ है।'उन्होंने कहा कि व्यापारिक सौदों का निपटान अपनी स्थानीय मुद्राओं में करने का मुद्दा भी समय-समय पर उठता रहा है।

अगले हफ्ते से शुरू होगा कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन

नईदिल्ली। इंडिया इंक के कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस पर सभी की नजरें टिकी हुई, क्योंकि कंपनियां अगले हफ्ते में अपने तिमाही नतीजे घोषित करने वाली हैं। ट्रेंड को फॉलो करते हुए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रमुख कंपनियां टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एचसीएल टेक्नोलॉजीज 12 जुलाई को अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी और साथ ही अर्निंग सीजन की भी शुरुआत करेंगी। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अनुमान लगाया है कि अप्रैल-जून तिमाही में निफ्टी की कमाई सालाना आधार पर 25 फीसदी बढ़ सकती है। इसके अलावा फर्म ने यह भी उम्मीद जताई है कि बिक्री और EBITDA में सालाना क्रमश: 4 फीसदी और 17 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। अर्निंग ग्रोथ को बीएफएसआई (बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा) और ऑटो क्षेत्रों द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा।

विलय से एचडीएफसी बैंक में आएगी मजबूती

तमाल बंद्योपाध्याय

टाइम्स बैंक का 26 फरवरी 2000 को एचडीएफसी बैंक में विलय हो गया था। यह भारतीय बैंकिंग कारोबार में पहला विलय था और यह इस दृष्टिकोण से भी अलग था कि सौदा शेयरों की अदला-बदली के माध्यम से हुआ था। इस विलय के बाद एचडीएफसी बैंक व्यवसाय एवं बाजार मूल्यांकन के लिहाज से बड़े बैंकों की सूची में शामिल हो गया।

इससे भी बड़ा सौदा एचडीएफसी बैंक ने फरवरी 2008 में किया। एचडीएफसी बैंक और सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब (सेंचुरियन पीओबी) दोनों ने विलय का सौदा किया और जो तब भारतीय बैंकिंग कारोबार के इतिहास में सबसे बड़ा विलय साबित हुआ। अब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक का आपस में विलय हुआ है। हालांकि, भारतीय वित्तीय तंत्र में यह सबसे बड़ा विलय नहीं है मगर बाजार मूल्य के लिहाज से इसे सबसे बड़ा जरूर कहा जा सकता है।

शुक्रवार को एचडीएफसी बैंक एवं इसके प्रवर्तक एचडीएफसी का संयुक्त बाजार पूंजीकरण 14.67 लाख करोड़ रुपये था। यह आंकड़ा सभी सूचीबद्ध बैंकों के संयुक्त बाजार पूंजीकरण के आधे से अधिक और सरकार नियंत्रित बैंकों के पूंजीकरण का डेढ़ गुना था। वैश्विक स्तर पर यह बैंकों के बीच बाजार पूंजीकरण के लिहाज से यह चौथा सबसे बड़ा आंकड़ा है।

दोनों इकाइयों में विलय की संभावना शुरू से ही थी। एचडीएफसी बैंक के निवेशक शुरू से ही आवास ऋण कारोबार के पक्ष में थे मगर एचडीएफसी भी इस कारोबार में थी इसलिए वह इसके लिए राजी नहीं हो रही थी। इसके अलावा नियमन से जुड़े कुछ विषय भी थे। इनमें सांविधिक तरलता

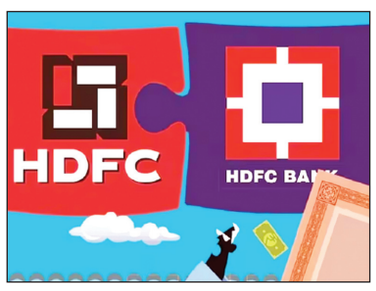

अनुपात (एसएलआर)- सरकारी बॉन्ड में बैंकों द्वारा किया जाने वाला अनिवार्य निवेश, नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)- जमा रकम का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखने की अनिवार्यता- और प्राथमिक क्षेत्र को ऋण आवंटन से जुड़ी शर्तें थीं।

उदाहरण के लिए एसएलआर अब 18 प्रतिशत और सीआरआर 4.5 प्रतिशत हैं। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित बैंक और गैर-बैंकिंग इकाइयों के नियमन में समानता आ रही है और आरबीआई ने आकार, गतिविधि और जोखिम आधारित (स्केल बेस्ड रेग्यूलेशन) उधारी नियमन प्रभावी कर दिए हैं। अब बैंकों और गैर-बैंकिंग इकाइयों दोनों के लिए परिसंपत्ति वर्गीकरण नियम लगभग समान हो गए हैं।

एचएफसी को कोई विशेष रियायत नहीं दी जा रही है। ऐसे में मूल कंपनी के साथ विलय कर एचडीएफसी को क्यों नहीं बड़ा और मजबूत बनाया जाए? इस विलय के पीछे यही सोच दिख रही है।

विलय के बाद बैंक का स्वरूप क्या होगा? मार्च 2023 के बहीखाते के अनुसार एचडीएफसी बैंक का परिसंपत्ति आधार 31.94 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा (आईसीआईसीआई बैंक का दोगुना मगर एसबीआई की तुलना में काफी छोटा)। इसका आवास ऋण खाता 6.71 लाख करोड़ रुपये (कंपनियों को दिए ऋण शामिल नहीं) के साथ बैंकिंग उद्योग में सबसे बड़ा हो जाएगा। इसकी तुलना में एसबीआई का आवास ऋण खाता 6.41 लाख करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई का 3.45 लाख करोड़ रुपये है।

विलय के बाद कंपनी और खुदरा ऋणों का अनुपात 58: 42 से कम होकर 50: 50 रह जाएगा। अधिक मात्रा में आवास ऋणों के बैंक के बहीखाते में आने के बाद असुरक्षित ऋणों का हिस्सा समग्र खाते में 11 प्रतिशत से कम होकर 7 प्रतिशत रह जाएगा और इसके खुदरा ऋण खाते में 27 प्रतिशत से कम होकर 15 प्रतिशत रह जाएगा। इससे बैंक के बही-खाते में मजबूती आएगी और ऋण पर लागत संभवत: कम हो जाएगी। एचडीएफसी बैंक के ऋणों की औसत अवधि भी कम हो जाएगी क्योंकि आवास ऋण औसतन छह वर्षों तक चलते हैं।

महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को टूट का डर

निरंजन परिहार

शिवसेना, एनसीपी में चौंकाने वाली टूट के बाद अब अगली बड़ी टूट क्या कांग्रेस में होगी? इस सवाल का जवाब सकारात्मक है। बहुत संभव है कि अब महाराष्ट्र कांग्रेस में भी बिखराव आ जाए। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता अजित पवार के पाला बदल कर सरकार में उपमुख्यमंत्री बन जाने के अत्यंत आश्चर्यजनक राजनीतिक घटनाक्रम को कांग्रेस में काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। पार्टी के बड़े नेता भी मान रहे हैं कि अजित पवार के बीजेपी के साथ चले जाने के बाद अगले साल होनेवाले चुनाव में हार-जीत का गणित बदल चुका है और इस कारण कांग्रेस विधायकों के लिए भी पालाबदल करके सत्ता के साथ जाने का रास्ता खुल गया है। रविवार से लेकर मंगलवार तक तीन दिनों से दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान और उसके प्रतिनिधियों तथा मुंबई में बैठे कांग्रेस नेताओं के बीच लगातार फोन घनघना रहे हैं। सतर्कता यह बरती जा रही है कि किसी को खबर तक नहीं लगे कि किस पर नजर रखी जा रही है और सावधानी यह भी कि पार्टी को लगातार एकजुट बनाए रखना है। खास ध्यान इस पर है कि कांग्रेस का कौनसा विधायक बीजेपी के किस बड़े नेता के संपर्क में है, किस विधायक पर किस बीजेपी नेता का प्रभाव है तथा कौन कौन से विधायक हार के गणित से डर कर किसी दूसरे रास्ते पर अपने कदम बढ़ा सकते हैं, इसका गहन आकलन किया जा रहा है। जानकारी इस बात की भी जुटाई जा रही है कि अजित पवार किस कांग्रेस नेता को अपने साथ लाने में सक्षम साबित हो सकते हैं। कांग्रेस में हालात सावधानी के हैं। दिल्ली में बैठा आलाकमान सतर्क है, और महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक सहमे हुए हैं क्योंकि सब के सब स्कैनर पर हैं। फोन पर किसी से खुलकर बात करना भी उनको नहीं सुहा रहा। महाराष्ट्र में कांग्रेस की नजर अब अपने ही विधायकों पर इसलिए है, क्योंकि आलाकमान को पता है कि पार्टी में प्रादेशिक नेताओं के बीच व्यक्तिगत स्तर पर काफी खींचतान है। विधायकों में असंतोष भी है। राजनीतिक विश्लेषक अभिमन्यु शितोले मानते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व इस तथ्य से भी बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ है कि एनसीपी में बड़ी टूट से प्रदेश के बदले हुए राजनीतिक हालात में कांग्रेस विधायकों को हार की चिंता सता रही है। शितोले मानते हैं कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस के ज्यादातर विधायकों के लिए अगला चुनाव जीतना मुश्किल होगा। ऐसे में हर विधायक सुरक्षित रास्ता अपनाना चाहता हैं। नई दिल्ली में एक दशक तक कांग्रेस मुख्यालय की राजनीतिक गतिविधियों के साक्षी रहे वरिष्ठ पत्रकार संदीप सोनवलकर मानते हैं कि कांग्रेस विधायकों के लिए अब भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा से दूरी बनाकर रखना कोई बड़ा कारण नहीं हैं। क्योंकि कांग्रेस पहले भी कट्टर हिंदुत्व की विचार रखने वाली शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार में सहभागी रही है। इस कारण से भी कांग्रेस के विधायकों के लिए शिवसेना, भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सामूहिक सरकार के साथ खड़े रहना ज्यादा आसान है। वैचारिक रूप से भी कांग्रेस सदा से राष्ट्रवादी कांग्रेस की सबसे करीबी पार्टी रही है। नई दिल्ली की नजर मुंबई पर इसी कारण है, क्योंकि उसे अपने विधायकों को साथ रखे रहना ज्यादा जरूरी हो गया है। हालात कांग्रेस में टूट के समर्थन में हैं और माहौल भी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के कई वर्तमान विधायक ऐसे हैं, जिनका बदले हुए राजनीतिक हालात में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अगला चुनाव लड़ना या जीतना दोनों ही लगभग बेहद मुश्किल है।

भाजपा-अकाली दल

आदिति फडणीस

इस सप्ताह के आरंभ में जब शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल यूरोप में दो सप्ताह की छुट्टियां बिताकर वापस आए तो उन्होंने पार्टी के सबसे महत्त्वपूर्ण जिलास्तरीय नेताओं की बैठक बुलाई। जब वह छुट्टियों पर थे तो ऐसी अटकलें सुनकर चकित थे कि शिअद और भारतीय जनता पार्टी (ब्ब्छ्क्क) दोबारा एक हो सकती हैं। इसके साथ ही ये अटकलें भी लगाई जा रही थीं कि आगामी लोकसभा चुनाव में दोनों दल कितनी-कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और यह भी कि कैबिनेट में कितने पदों की पेशकश की जाएगी।

दोनों दलों के नेताओं की मानें तो अब तक उनके बीच कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई है। दोनों चिंतित हैं और समस्याएं बेशुमार हैं। पहली बात तो यह कि शिअद की राजनीतिक स्थिति खासी कमजोर है, हालांकि पार्टी इसे स्वीकार नहीं करना चाहती। हालांकि यह कहना अतिरंजित होगा कि पार्टी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। यह पार्टी गुरुद्वारों पर नियंत्रण रखती है और उसके साथ अत्यंत मुखर प्रवासी समुदाय है। पार्टी को धन की कोई कमी नहीं है।

लेकिन पार्टी 2017 और 2022 में लगातार दो विधानसभा चुनाव हार चुकी है और इस समय विधानसभा में उसके केवल तीन विधायक हैं। जालंधर लोकसभा सीट के लिए हुए हालिया उपचुनाव में उसकी समस्या स्पष्ट रूप से सामने आई- शिअद तीसरे स्थान पर रही जबकि भाजपा चौथे।

दोनों दलों को क्रमश-17.85 फीसदी और 15.19 फीसदी मत मिले। जबकि विजेता आम आदमी पार्टी को 34.05 फीसदी तथा कांग्रेस को 27.85 फीसदी वोट मिले। शिअद और भाजपा को मिलाकर 33.04 फीसदी मत मिले।

परंतु शिअद की अपनी शिकायतें भी हैं। एक समय उसकी मित्र और साझेदार रही भाजपा अब उसे बहुत नुकसान पहुंचा रही है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (ष्ठस्त्रस्ष्ट) के प्रमुख मनजिंदर सिंह सिरसा, शिअद के पूर्व विधायक दीदार सिंह भट्टी, एसजीपीसी के सदस्य सुरजीत सिंह गढ़ी और कद्दावर अकाली नेता रहे स्वर्गीय गुरुचरन सिंह तोहड़ा के पोते कंवरवीर सिंह आदि सभी को भाजपा ने अपने पाले में कर लिया।

हालांकि भट्टी और कंवरवीर सिंह दोनों को 2022 के विधानसभा चुनाव में लड़ाया गया था और दोनों को पराजय मिली थी। सुरजीत सिंह गढ़ी शिअद की राजनीतिक मामलों की समिति तथा एसजीपीसी के सदस्य थे।

सुखदेव सिंह ढींडसा के शिअद (संयुक्त) का भाजपा के साथ गठबंधन है और शिअद के नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी भी भाजपा की ही देन है। संक्षेप में कहें तो भाजपा शिअद पर लगातार हमले कर रही है। भाजपा के अंदर की बात करें तो शिअद को लेकर दो तरह के विचार हैं।

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दोनों दलों के बीच नए सिरे से गठबंधन की संभावना को बार-बार खारिज किया है। जमीन की बात करें तो पंजाब में भाजपा की वृद्धि और विकास तथा उसकी प्रतिष्ठा को शिअद के साथ जुड़ाव के चलते झटका लगा है। कुछ अन्य लोग चिंता जताते हैं कि पंजाब में तथा बाहर भी आधार सिमट रहा है।

ऑस्ट्रेलिया में करीब दो लाख सिख हैं और उनकी आबादी देश की जनसंख्या का 0.8 फीसदी है। वहां की जनगणना के अनुसार पंजाबी ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज बढ़ती भाषा है। परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में जो आयोजन किया वहां कुल कितने सिख मौजूद थे केवल छह।

भाजपा नेता कहते हैं कि सिखों की स्मृति बहुत दीर्घकालिक होती है। उन्होंने अभी तक जनरल डायर को माफ नहीं किया है जिसने सन 1919 में जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश दिया था। 2020-21 में भाजपा सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों का जिस तरह दमन किया था वह भी उन्हें याद है। ऐसे में भाजपा इन मुश्किल हालात से भी कुछ हासिल कर सकती है और शिअद से दूरी बनाकर रख सकती है लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि शिअद और भाजपा दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है।

भाजपा ने हाल ही में सुनील जाखड़ को पंजाब प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है और यह बात इसी हकीकत की स्वीकारोक्ति है। जाखड़ हिंदू हैं और उन्होंने बमुश्किल कुछ महीने पहले भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा ने अमरिंदर सिंह या किसी अन्य सिख नेता को यह पद नहीं दिया जो दशकों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। शिअद नेताओं का दावा है कि पार्टी में इस नियुक्ति को लेकर जबरदस्त असंतोष है। भाजपा के तमाम नेता कार्यकर्ता खुद इस पर खामोश हैं।

दोनों पूर्व सहयोगियों के बीच असंतोष के क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं। शिअद समान नागरिक संहिता के खिलाफ है। पुराने मुद्दे भी बने हुए हैं- देशद्रोह और हत्या जैसे मामलों में सजायाफ्ता लोगों मसलन बलवंत सिंह राजोआना की रिहाई पर निर्णय का लंबित होना। राजोआना पर पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का दोष सिद्ध है उसे 2007 में ही फांसी की सजा का आदेश हो चुका है। गृह मंत्रालय बार-बार उसकी दया याचिका पर निर्णय टालता आ रहा है। कुछ अन्य लोग देशद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और 33 वर्षों से जेल में हैं।

भाजपा का अनकहा एजेंडा है राजनीति को गुरुद्वारों से अलग करना। फिलहाल वह आम आदमी पार्टी को लेकर संतुष्ट है कि वह उसका ही काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर से गुरबाणी के प्रसारण को फ्री टु एयर करने का निर्णय लिया है जिसे राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है। पहले इस पर एक चैनल का एकाधिकार था जो कथित रूप से बादल परिवार का है। भाजपा ने इस निर्णय का समर्थन किया है कि यह प्रसारण एक से अधिक चैनलों पर होना चाहिए लेकिन उसने आप के एसजीपीसी अधिनियम 1925 में संशोधन के निर्णय का यह कहकर विरोध किया है कि यह केवल संसद ही कर सकती है।

शिअद का कहना है कि आखिरकार वार्ता तो होगी लेकिन यह बातचीत ठंडी और भावनारहित होगी। कहा जा रहा है कि सुखबीर सिंह बादल 'अंग्रेजी बोलने लगेंगे' और इसमें वह गर्माहट नहीं नजर आएगी जो अटल बिहारी वाजपेयी और प्रकाश सिंह बादल में नजर आती थी। उनका कहना है कि सिखों के लिए आत्मसम्मान सबसे बढ़कर है और इस समय राज्य में अकाली दल की राजनीतिक तकदीर जिस स्थिति में है उसमें अहंकार से बात नहीं बनेगी। इस बीच भाजपा की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

कृपया इनसे सीखें

ऑफ ऑल 22 विषयों में किया एमए

पढ़ाई के प्रति जज्बा चाहे जितना मजबूत हो, लोग ज्यादा से ज्यादा तीन-चार विषयों में मास्टर डिग्री ले पाते हैं। पर ऋषिकेश में रहने वाले डॉ. रामकिशोर राय ने 22 विषयों से एमए कर डाला। इन अनोखी उपलब्धि के बाद भी डॉ. राय की सरस्वती साधना अभी थमी नहीं है। वह राजस्थान से एलएलएम कर रहे हैं। ऋषिकेश के पास श्यामपुर में स्थित दून इंस्टीट्यूट की बीएड फैकल्टी में शिक्षा विभाग के प्रोफेसर डॉ. रामकिशोर राय 64 की उम्र में भी ताजगी से भरे हुए है। प्राथमिक शिक्षा अपने गाँव से करने के बाद उन्होंने 1967 में हिंदी से एमए किया। इसके बाद तो डिग्रियों की जो सफर शुरू हुआ वह आज तक नहीं थमा।

डॉ. रामकिशोर राय अपने सेवा काल में पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बिहार में प्रोफेसर और रीडर के पद पर रहे। सेवा निवृत्ति के बाद वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, हिमाचल विश्वविद्यालय, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, उत्तराखंड विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय आदि में भी प्रोफेसर रहे। वर्तमान में वह गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध दून इंस्टीट्यूट में शिक्षा विभाग में प्रोफेसर हैं। उन्हें मदर टेरेसा और इंदिरा गांधी सद्भावना अवार्ड से नवाजा जा चुका है। डॉ0 राय आज भी रोजाना चार घंटे अध्ययन जरूर करते हैं। दून इंस्टीट्यूट के निदेशक सीएम डोभाल का भी कहना है कि ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बिरले ही होते हैं। इन विषयों में हैं परास्नातक- हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, पाली, अंग्रेजी, भोजपुरी, प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, शिक्षा, इतिहास, मनोविज्ञान, भूगोल, दर्शन शास्त्र, पुरातत्व एवं संग्रहालय विज्ञान, धर्मशास्त्र, नाट्य शास्त्र, साहित्यचार्य, संगीत, एम.कॉम और एम. एड है।

आज की महत्वपूर्ण घटनाएं

1981 निन्टेंडो ने आर्केड गेम डोंकी कोंग जारी किया, जिसमें मारियो की शुरुआत हुई, जो वीडियो गेम के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक था।

1991 दक्षिण अफ्रीका को ओलंपिक खेलों में दोबारा भाग लेने की अनुमति मिली।

2002 इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में अफ्रीकी संघ की स्थापना। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थाबो म्बेकी इसके पहले अध्यक्ष बने।

2006 साइबेरिया के इरकुर्त्सक हवाई अड्डे के रनवे पर शिबिर एयरलाइंस ए 310 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम से कम 122 लोगों की मौत।

2008 इस विश्वास के तहत कि इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका अपने परमाणु कार्यक्रम पर हमला करने के लिए तैयार थे, ईरान ने ग्रेटप्रॉपेट III मिसाइल परीक्षण और युद्ध खेल अभ्यास किया।

2011 अफ्रीका का सूडान दो हिस्सों में बंट गया। दक्षिणी हिस्सा रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान बना।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् (भाग-2)

गतांक से आगे...

ब्रह्म से अव्यक्त, अव्यक्त से महत, महत् से अहंकार, अहंकार से पाँचों तन्मात्राएँ, पंच तन्मात्राओं से पंचमहाभूत और पंच महाभूतों के द्वारा ही यह सम्पूर्ण विश्व प्रादुर्भूत हुआ है। वह अखिल (विश्व) क्या है? यह (पंच) भूतों के विकार द्वारा प्रादुर्भूत विभाग स्वरूप है। भूतों के विकार द्वारा एक ही पिण्ड के विभाग किस तरह से होते हैं? उन भिन्न भिन्न भूतों के कार्य एवं कारण भेद के द्वारा अंश तत्त्व, वाचक- वाच्य स्थान भेद, विषय, देवता, कोश भेद आदि के आधार पर विभाग कहे गये हैं। अगले मंत्रों में पंचभूतों के भेद क्रम स्पष्ट किये गये हैं- आकाश के पाँच भेद हैं- अन्त:करण, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार समान, उदान, व्यान, अपान, प्राण आदि ये पाँच वायु हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा एवं घ्राणेन्द्रिय ये (ज्ञानेन्द्रियाँ) अग्नि से प्रकट होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-ये पाँच (तन्मात्राएँ) जल तत्त्व से प्रादुर्भूत होती हैं। वाणी, हाथ, पैर, गुदा एवं उपस्थ- ये (कर्मेन्द्रियाँ) पृथ्वी के द्वारा प्रादुर्भूत हैं।

ज्ञान, संकल्प, दृढ़ निश्चय, अनुसंधान एवं अभिमान ये आकाश तत्त्व के कार्य और अन्त:करण के विषय हैं। समीकरण (सन्तुलन), उन्नयन (ऊर्ध्वगति देना), ग्रहण करना, श्रवण (श्रवण प्रवाहित या निष्कासित करना), उच्छ्वास (श्वास ग्रहण करना एवं छोड़ना) ये सभी वायु तत्त्व के कार्य तथा प्राण आदि के विषय कहे गये हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध आदि ये सब अनि तत्त्व के कार्य और ज्ञानेन्द्रियों के विषय बतलाये। गये हैं। ये सब (तन्मात्रा रूप में) जल तत्त्व के आश्रित हैं। वचन (बोलना), दान, गमनागमन, विसर्जन तथा आनन्द पृथ्वी तत्त्व के कार्य एवं कर्मेन्द्रियों के विषय हैं। कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय के विषयों में प्राण एवं तन्मात्राओं के विषय अन्तर्भूत हैं। मन एवं बुद्धि में ही चित्त और अहंकार अन्तर्भूत हैं। अवकाश (रिक्त स्थान), हटाना (गमनागमन गतिशीलता), दर्शन (देखना), पिण्डीकरण (मिलाना - पिण्ड बना देना), धारणा (धारण करना) आदि ये सभी (क्रमश: आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी तत्त्वों से सम्बन्धित) सूक्ष्मातिसूक्ष्म तन्मात्राओं के विषय हैं।

क्रमश: ...

राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस

हर साल 10 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देश में मछली किसानों, मछुआरों और मछली पालन से जुड़े अन्य हितधारकों के काम को सम्मान और समर्थन देना है।

देश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और 'नीली क्रांति' द्वारा, भारत सरकार ने देश में आर्थिक क्रांति लाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार ने मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार और अपशिष्ट में कमी लाते हुए किसानों की आय बढ़ाने की परिकल्पना की है।

भारत में में विभिन्न प्रकार के अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य संसाधनों को स्थायी रूप से उपयोग करने की क्षमता के साथ, मछली पकड़ना और जलीय कृषि देश की महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों में से एक है।

देश में मछली पालन एक बहुत बड़ा उद्योग है। देशभर में लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए मछली पालन और इससे संबंधित कार्यों पर निर्भर है। इसलिए राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस एक महत्वपूर्ण विषय है।

देश में पहली बार 10 जुलाई, 1957 को प्रोफेसर डॉ. हीरालाल चौधरी और उनके सहयोगी डॉ. अलीकुन्ही ने ओडिशा के अंगुल में प्रमुख कार्प्स के सफल प्रेरित प्रजनन में कार्प पिट्यूटरी हार्मोन को निकालने में सफलता हासिल की थी। 10 जुलाई, 1957 को दोनों वैज्ञानकों ने हाइपोफिजेशन का प्रदर्शन किया था, जो भारतीय मेजर कार्प्स में प्रजनन को प्रेरित करने की एक तकनीक है। प्रोफेसर चौधरी और डॉ अलीकुन्हीं के इस महत्वपूर्ण योगदान की याद में ही हर साल भारत में मत्स्य किसान दिवस का आयोजन किया जाता है।

साल 2001 में, भारत सरकार ने 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली पालन दिवस के रूप में नामित किया था। इसका उद्देश्य एक्वाकल्चर में शामिल लोगों, जैसे- मछुआरे, मछली किसान, मत्स्य विशेषज्ञ और अन्य हितधारकों के प्रति के लिए समर्थन व्यक्त करना था। इसके बाद साल 2001 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की देखरेख में देश का पहला राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस समारोह मनाया गया। इस महत्वपूर्ण समारोह में मत्स्य पालन शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान, सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन ने भी भाग लिया था।

राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाने का उद्देश्य देश के मत्स्य उद्योग के विकास के लिए मछली किसानों, एक्वाप्रेन्योर (जल क्षेत्र में व्यवसायी) और मछुआरों द्वारा किए गए योगदान को पहचानना है और स्थायी मत्स्य पालन स्टॉक और मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए, देश को अपने मत्स्य पालन संसाधनों का प्रबंधन करने के तरीके को बदलने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

मत्स्य उद्योग से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और सामान्य विकास बहुत प्रभावित होता है। मत्स्य उद्योग, जिसे कभी नवोदित विकासशील उद्योग के रूप में जाना जाता है, विकास के माध्यम से भारी क्षमता पैदा करने की स्थिति में है जो न्यायसंगत और समावेशी दोनों है।

इस्राइल और फिलस्तीन के मिजाज भी बदल रहे

चंद्रभूषण

बीते बीस वर्षों का सबसे बड़ा सैन्य अभियान फिलस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में चलाकर इस्राइली सैनिक वापस बैरकों में लौट गए हैं। लेकिन अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की यह चेतावनी दोहराते हुए कि इसे एक बार की अलग-थलग गतिविधि न समझा जाए, क्योंकि ऐसी कार्रवाइयां फिलस्तीनी बस्तियों में आतंकी अड्डों के समूल नाश तक चलती ही रहेंगी। इस्राइल की सैन्य कार्रवाई का केंद्र इस बार जेनिन नाम की बस्ती बनी, जो वेस्ट बैंक के उत्तरी छोर पर है और पिछले डेढ़ वर्षों से वहां जारी सैन्य टकराव को लेकर अक्सर चर्चा में आती रही है। बहरहाल, 1948 में इस्राइल की स्थापना के समय से ही चलते आ रहे इस टकराव को लेकर कुछ बातें गौर करने लायक हैं। कुछ समय पहले तक विस्थापित फिलस्तीनियों के खिलाफ इस्राइल की सरकारी हिंसा को लेकर पूरी दुनिया में, खासकर अरब देशों में जैसा आक्रोश देखा जाता था, वह अब बीते दिनों की बात हो चुका है। फिर भी एक न्यायसंगत मुद्दे के रूप में इसकी कुछ न कुछ अनुगूंज आज भी बनी हुई है। 2016 की वार्ता टूटने के बाद इस्राइल की कोशिश भी अपनी पहचान को दिन-रात की इस लड़ाई से ऊपर उठाने की रही है। इसीलिए पिछले डेढ़ वर्षों में बार-बार ऐसा देखा गया है कि फिलस्तीनी इलाकों में अपनी फौज तो वह पूरी तैयारी से उतारता है, लेकिन उसके फौजी हर बार दो-तीन दिन में ही तयशुदा ठिकानों को तहस-नहस करके वापस लौट आते हैं।

शायद इसके पीछे सोच यह है कि टकराव को भावनात्मक मुद्दा न बनने दिया जाए। मामला लंबा नहीं खिंचेगा तो अरब देशों में फिलस्तीनियों को सैनिक और आर्थिक मदद देने का जनदबाव नहीं बनेगा और बाहर से मदद नहीं आई तो फिलस्तीनी प्रतिरोध कोई बड़ी शक्ल नहीं ले पाएगा। हाल तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि अरब देशों के साथ कभी इस्राइल के सामान्य कूटनीतिक रिश्ते बहाल हो पाएंगे। लेकिन अभी संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में न केवल इस्राइली दूतावास खुल चुका है बल्कि आई2यू2 संगठन के रूप में भारत, अमेरिका, यूएई और इस्राइल के बीच काफी स्वस्थ और बहुआयामी आर्थिक-व्यापारिक रिश्ते कायम हो चुके हैं। सऊदी अरब और ईरान पूरी दुनिया में सुन्नी और शिया फिरकों की धुरी बने हुए थे, लेकिन चीन की कोशिशों से अभी उनमें सुलह हो गई है। अर्से बाद जेद्दा और तेहरान में एक-दूसरे के दूतावास दिखाई देने लगे हैं। दुनिया में इस इलाके की चर्चा लड़ाई-झगड़े के अलावा सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों के लिए होती थी, लेकिन बहुधंधीपने की मुहिम अभी लगभग हर देश में चल रही है। इसमें कुछ भूमिका यहां से अमेरिका के हाथ खींचने और उससे छूटी जगह में भारत और चीन के दखल बनाने की भी है।

इस्राइल चाहे तो इस मौके का फायदा उठाकर फिलस्तीनियों से अपने टकराव को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। इसके लिए उसको वहीं से बात आगे बढ़ानी होगी, जहां तक यह बराक ओबामा के समय में पहुंच गई थी। इस्राइल और फिलस्तीन, दो देश होने चाहिए, इस पर एक स्तर की सैद्धांतिक सहमति इस्राइली दायरों में भी बन गई थी। दूसरी तरफ फिलस्तीनी नेतृत्व को भी इस बात का कुछ अंदाजा हो गया होगा कि उसके लिए हालात दिनोंदिन बेहतर नहीं हो रहे। यासिर अराफात के समय में फिलस्तीनी आजादी के मुद्दे पर दुनिया में जितना बड़ा जनसमर्थन बना हुआ था, 87 वर्षीय महमूद अब्बास अब उसका एक चौथाई भी नहीं जुटा पाते। महमूद अब्बास भी अब ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं। उनके आंख मूंदने के बाद फिलस्तीन में कोई कद्दावर नेतृत्व आ सकेगा, इसकी संभावना कम ही है।

गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और पूर्वी येरुशलम में मौजूद हर फिलस्तीनी बस्ती में अभी कम से कम पांच गुट मौजूद हैं। दो फतह ग्रुप, एक हमास ग्रुप, एक ईरान के समर्थन वाला इस्लामिक जेहाद ग्रुप और एक संदेहास्पद सा इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने का दावा करने वाला ग्रुप। इन सभी ग्रुपों में एक-दूसरे से ज्यादा उग्र दिखने की होड़ मची रहती है, जिससे बड़ा नेतृत्व कभी नहीं निकलेगा। भारत के संबंध फिलस्तीन के साथ हमेशा ही अच्छे रहे हैं और इस्राइल के साथ भी अभी काफी गहरे हो गए हैं। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच संवाद की एक पहल हमारी ओर से जरूर होनी चाहिए। एक संभावना है कि अरब-ईरान समझौते की तरह ही इस्राइल-फिलस्तीन सुलह की सबसे अहम कोशिश भी अभी के माहौल में चीन की ही तरफ से हो। महमूद अब्बास हाल में चीन होकर लौटे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू भी जल्द ही चीन की यात्रा करने वाले हैं।

1948 में जब फिलस्तीनी बस्तियों को उजाड़कर इस्राइल को बसाने की प्रक्रिया शुरू हुई और फिलस्तीनियों से एका दिखाने के नाम पर इजिप्ट ने भूमध्य सागर के किनारे की गाजापट्टी, जॉर्डन ने जॉर्डन नदी का पश्चिमी किनारा और सीरिया ने गोलन पहाड़ियां फिलस्तीनियों को सौंप दीं तो इन नए इलाकों में फिलस्तीनियों को बसाकर इतने पर भी झगड़ा शांत हो सकता था। लेकिन 1967 में संयुक्त अरब सेनाओं के खिलाफ जंग जीतने के बाद इस्राइल ने नए इलाकों में भी अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दीं और फिलस्तीनियों के पास उनकी अपनी जमीन के नाम पर सिर्फ कुछ चकत्ते छोड़ दिए।

इतने समय में आम इस्राइली को इस बात का एहसास हो गया है कि एक देश के रूप में उसका अस्तित्व जबरन घेरी गई जमीनों पर निर्भर नहीं करता। उनका समाज मुख्यत: विज्ञान, तकनीकी और नई खोजों पर आधारित है। हमेशा अमेरिका के भरोसे रहने के बजाय पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर वे बहुत आगे जा सकते हैं। भारत अभी दुनिया के कुछ ऐसे गिने-चुने देशों में है, जिसके इस्राइल, फिलस्तीन और ज्यादातर अरब देशों से बहुत गहरे संबंध हैं। निकट भविष्य में पूरा खाड़ी क्षेत्र भारत के साथ हजार रिश्तों में बंधा नजर आएगा। ऐसे में इस इलाके का सबसे पुराना झगड़ा सुलझने की शुरुआत भारत की ही पहल पर हो, इससे अच्छी बात और क्या होगी।

बापू की दिनचर्या

सायंकालीन आहार (भाग-2)

गतांक से आगे...

लंदन में अपनी अस्वस्थता के समय डॉ. एलिन्सन के परामर्श के अनुसार शाम के आहार में बापू दो चम्मच भात के साथ पूर्वोक्त रीति के कच्चा साग, भिंगाए हुए अंजीर, केले तथा गेहूँ के आटे की रोटी का छोटा- सा टुकड़ा लेते। कोचरब के सत्याग्रह आश्रम में शाम को ठीक पाँच बजे भोजन होता। . बारहों मास वहाँ यह क्रम चलता। वहाँ बापू पहले सब आश्रमवासियों को खिलाकर स्वयं खाने बैठते। साबरमती में भी सायंकालीन आहार का यही समय था। वहाँ शाम को खिचड़ी, डबल रोटी और साग- ये चीजें विशेष रूप से बनतीं। सेवाग्राम में वे साढ़े पाँच-छह बजे भीजन करते। सन् 1945 से 46 के मध्य वहाँ वे शाम का भोजन पाँच बजे कर लिया करते। आगा खाँ महल में बा की बीमारी के अंतिम दिनों में वे शाम को लगभग साढ़े छह बजे आहार ग्रहण करते, जिसमें केवल आठ औंस दूध और 1 आँस गुड़ होता। बापू चीनी के बदले गुड़, अंजीर एवं खजूर का उपयोग करते बाजारू गुड़ पर मक्खियों आदि के बैठने तथा उसमें मिट्टी, घास आदि का अंश प्राय: रह जाने के कारण, उनके गुड़ को पानी में घोल और कपड़े से छानकर उबाला और गुड़ शेष रहने पर उतार लिया जाता। इस प्रकार उसकी शुद्धि हो जाती। जब वे बोलते-बोलते थक जाते, तब भी शक्ति बनाए रखने के लिए गुड़ खाया करते। नोवाखाली में बापू सायंकाल का आहार पाँच बजे किया करते, जो बिलकुल दिन के जैसा होता। दिल्ली में अंतिम दिनों में रात्रि का आहार वे शाम को चार बजे के लगभग कर लिया करते, जिसमें उबाला हुआ साग, थोड़ा संतरा या इसी तरह का कोई रसदार फल और सोलह औंस दूध-ये चीजें होतीं। अपने अंतिम दिन का आहार उन्होंने साढ़े चार बजे ही कर लिया था, जिसमें चौदह औंस बकरी का दूध, चौदह औंस सब्जी का रस और तीन संतरे थे।

नकली राम भक्तों की खुल गई पोल : मरकाम

■ छत्तीसगढ़ आए और भाचा राम और माता कौशल्या को याद तक नहीं किया

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर आरोपों की झड़ी लगाई। इन आरोपों को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि पीएम मोदी और भाजपा ने छत्तीसगढ़ आकर न भाचा राम को याद किया, ना माता कौशल्या का स्मरण किया। भाजपा के इस कृत्य के कारण उनकी नकली राम भक्ति की पोल खुल गई है। मरकाम ने कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी को पूछे जाने वाले 21 सवालों के जवाब भी नहीं देने का आरोप पीएम मोदी पर लगाया है।

प्रधानमंत्री ने एक बार फिर बोला झूठ-छत्तीसगढ़ को 7600 करोड़ रुपये की सौगात देने के बाद पीएम मोदी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर एक एक कर कई आरोप लगा दिए। छत्तीसगढ़ की जनता को मन मोहने के लिए छत्तीसगढ़ी में सरकार बदलने की अपील पीएम मोदी ने की। मोदी के छत्तीसगढ़ से वापसी के बाद प्रदेश कांग्रेस ने प्रेसवार्ता कर पीएम मोदी पर कई आरोप लगाए। इसकी शुरुआत उन्होंने पीएम मोदी को झूठा बोलकर की। मरकाम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से झूठ बोलकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार-तार किया। उन्होंने प्रदेश के जन हितैषी सरकार के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए। उनके द्वारा लगाए गए सारे आरोप निरर्थक है।

मरकाम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के किसानों को 10 दिन के भीतर कर्ज माफी का लाभ देने के लिए गंगाजल की सौगंध खाई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ ग्रहण के 2 घंटे के भीतर ही प्रदेश के 20 लाख किसानों को कर्ज मुक्त किया। मरकाम ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में मोदी सरकार अपने सरकार की उपलब्धि बताने में नाकाम रही और हमेशा की तरह जनता को गुमराह करती रही। भाजपा के दूसरे नेताओं की तरह प्रधानमंत्री ने भी झूठ बोला कि छत्तीसगढ़ की धान खरीदी में 80 प्रतिशत योगदान केंद्र सरकार का है जबकि हकीकत ये है कि धान खरीदी में केंद्र का योगदान नहीं के बराबर है।

मरकाम ने कहा कि राज्य सरकार अपने दम पर धान की खरीदी करती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने वादा किया था कि 2500 रुपये प्रति क्विंटल में धान की खरीदी करेगी, मोदी की सरकार ने अडंगा लगाया कि यदि समर्थन मूल्य से एक भी रुपया ज्यादा देंगे तो छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पूल का चावल नहीं लेंगे। राज्य सरकार ने मोदी सरकार के धान खरीदी की विरोधी नीति के काट के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की।

घोषणा पत्र के 95 प्रतिशत वादे पूरे, शराबबंदी भी जल्द- मरकाम ने बताया कि कांग्रेस की सरकार ने 2018 के घोषणा पत्र के 95 प्रतिशत वादों को पूरा किया है। कांग्रेस की सरकार शराबबंदी के दिशा में आगे बढ़ चुकी है। डेढ़ सौ से ज्यादा शराब दुकानों को बंद किया गया है। शराबबंदी के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि जनहानि ना हो। कांग्रेस की सरकार ने पेसा के नियम बनाकर पांचवी अनुसूची क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शराबबंदी करने का अधिकार दे दिया है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ा है। 15 साल के रमन भाजपा शासनकाल कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, घोटालों का काला अध्याय थी। उन 15 साल में छत्तीसगढ़ 30 साल पीछे चला गया था। आज 5 साल में छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ा।

एआईसीसी के सचिव एवं प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव ने कहा कि मणिपुर जल रहा है। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को वहां जाने का समय नहीं मिला। अब जब छत्तीसगढ़ में चुनाव पास है तो पीएम मोदी छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। यादव ने कहा कि नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प लेकर कांग्रेस की सरकार ने 2018 में सफर शुरू किया था। इन साढ़े 4 सालों में कांग्रेस सरकार ने ना सिर्फ अपने 95 प्रतिशत वादे पूरे किए थे बल्कि 51 नई योजनाओं शुरू कर छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ का खेलकूद, छत्तीसगढ़ लोकगीत के लिए काम शुरू किया। यहां की संस्कृति के हिसाब से छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है।

संक्षिप्त समाचार

बिना जानकारी दिए हड़ताल करने वाले कर्मचारियों की कटेगी सैलरी

रायपुर। प्रदेशभर के सरकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल पर थे। ऐसा कर्मचारी संगठनों ने बताया। वहीं इससे सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए विभाग के अपर सचिव अंशिका ऋषि पाण्डेय ने सभी विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्तों, कलेक्टर्स को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा है। बगैर जानकारी ड्यूटी से गायब रहे थे ऐसे लोगों की सैलरी भी कटेगी। चूंकि आगे विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है,ऐसे में विभाग की ओर से सख्ती बरता जाना स्वाभाविक भी है।

मुख्यमंत्री से बस्तर जिला सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में सांसद श्री दीपक बैज के नेतृत्व में बस्तर जिले के सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को बस्तर के विकास के लिए राज्य शासन से मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में बस्तर जिले के कोया समाज के अध्यक्ष श्री हिड़मा कवासी, मुरिया समाज अध्यक्ष श्री जगदीश मौर्य, धुरवा समाज अध्यक्ष श्री पप्पू राम नाग, माहरा समाज अध्यक्ष श्री सोनाराम नाग सहित आदिवासी समाज के अन्य सदस्य मौजूद थे।

जस्टिस कोशी की तेलंगाना जाने की कॉलेजियम ने की अनुशंसा

बिलासपुर। विगत 10 वर्षों से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पदस्थ वरिष्ठ जस्टिस पी सैम कोशी का उनकी मांग पर तेलंगाना हाईकोर्ट में तबादला किए जाने की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की है। इससे पूर्व उनका स्थानांतरण मध्यप्रदेश किया गया था लेकिन जस्टिस कोशी ने मध्यप्रदेश की जगह अन्य किसी भी राज्य में स्थानांतरण की इच्छा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को बताई थी। सुप्रीम कोर्ट की प्रधान न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने पहले उनका स्थानांतरण मध्य प्रदेश किया था लेकिन कोशी ने इच्छा जताई कि उन्हें मध्यप्रदेश छोड़कर किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित किया जाए। इस पर कोलोजियम ने उनका स्थानांतरण तेलंगाना हाई कोर्ट में करने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की है।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह को फिर से छत्तीसगढ़ लाने की तैयारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राजधानी रायपुर में आयोजित सभा आशा से बढ़कर सफल रही। मौसम खराब होने तथा लगातार बारिश के बाद भी शहर में प्रदेश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं की एकजुटता और चुनावी हुंकार और उत्साह देख भाजपा नेताओं ने राहत की सांस ली है। पीएम श्री मोदी के ठीक पहले केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राजधानी पहुंचकर भाजपा नेताओं को चार्ज किया था। भाजपा सूत्रों ने बताया कि अमित शाह को एक बार फिर से छत्तीसगढ़ लाने की तैयारी की जा रही है। बताया जाता है कि श्री शाह छत्तीसगढ़ आकर चुनावी बिसात पर अपने मोहरे फिट कर सकते हैं। अभी चुनाव के मद्देनजर कुछ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव के मद्देनजर कार्य विभाजन और जवाबदेही तय करना काफी जरूरी हो गया है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को बूस्ट करना भी जरूरी है। यही कारण है कि श्री शाह जल्द छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं।

अमृतसर-बिलासपुर डाउन एक्सप्रेस 5 घंटे देरी से पहुंची

राजनांदगांव। शनिवार को अमृतसर-बिलासपुर (18238) डाउन एक्सप्रेस 5 घंटे की देरी से राजनांदगांव पहुंची। स्थानीय स्टेशन में उक्त ट्रेन का तय समय सुबह लगभग 6.30 बजे है। बिलासपुर के लिए यह ट्रेन अमृतसर से 4 घंटे की देरी से रवाना हुई। अमृतसर में ट्रेन का निर्धारित समय शाम 4 बजे है। तकरीबन रात 8 बजे 4 घंटे की देरी से ट्रेन को बिलासपुर के लिए रवाना किया गया। अपने गंतव्य के लिए निकली यह ट्रेन रास्ते में एक घंटा और विलंब से चली। जिसके चलते 5 घंटे की भारी लेटलतीफी के बाद सुबह 11 बजे उक्त ट्रेन राजनंदगांव पहुंची। बताया जा रहा है कि रास्ते में पटरियों के मेन्टेनेंस का हवाला देकर ट्रेन को देरी से रवाना किया गया। रोजाना ज्यादातर ट्रेनें घंटो विलंब से चल रही है।

नक्सल इलाकों में प्री कास्ट तकनीक से होगा सड़कों और पुलों का निर्माण : गडकरी

■ ऐसी तकनीक और सामग्री का उपयोग करना चाहिए कि सड़कों का 20-25 साल तक रखरखाव करने की जरूरत ही न पड़े

रायपुर। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लागत पर नियंत्रण और कानून एवं व्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्री कास्ट तकनीक के इस्तेमाल से सड़कों और पुलों के निर्माण की जरूरत पर जोर दिया है। इंडियन रोड कांग्रेस की बैठक में उन्होंने कहा कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की पूरी रक्षा करते हुए निर्माण के नए तौर-तरीकों को अपनाने की जरूरत है। गुणवत्ता में कोई कमी लाए बिना आधुनिक तकनीक और नई पहल के साथ लागत घटाई जा सकती है।

गडकरी ने कहा कि बांस के क्रैश बैरियर का प्रयोग ऐसी ही एक पहल है, जो सुरक्षा के हर मानक पर खरी उतरी है। इसे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे समेत कई राजमार्गों और एक्सप्रेस वे में अमल में लाया जा रहा है। गडकरी ने सड़क निर्माण में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक तथा स्टील स्लैग जैसी सामग्री का इस्तेमाल बढ़ाए जाने की जरूरत पर जोर दिया।

ऐसी तकनीक और सामग्री का उपयोग करना चाहिए जिससे सड़कों का 20-25 साल तक रखरखाव करने की जरूरत ही न पड़े। इसके लिए तारकोल से बनने वाली सड़कों पर एक निश्चित मोटाई की ह्वाइट टापिंग के इस्तेमाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रयोग कई जगह सफल रहा है। इसने सड़कों को 25 साल तक रखरखाव की सुविधा दी है।

गडकरी ने बैठक में यह सुझाव दिया कि अगर किसी स्ट्रक्चर या सड़क के साथ दुर्घटना होती है तो जांच समिति और आयोग की रिपोर्ट के साथ ही वहां हुई गलती के वास्तविक कारणों और उसे रोकने के उपायों को अलग से प्रकाशित किया जाना चाहिए। इसे सभी राज्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

इसके लिए जरूरी नहीं है कि किसी अफसर का नाम लिया जाए, लेकिन यह सभी को जानना जरूरी है कि गलती क्यों हुई और कमी क्या रह गई। महाराष्ट्र में अगर कोई गलती होती है तो उसे छत्तीसगढ़ में क्यों दोहराया जाए? गडकरी का यह सुझाव हाल में कई पुलों के साथ हुए हादसों के संदर्भ में अहम है।

कांग्रेस का एक दिवसीय मौन सत्याग्रह 12 को गांधी मैदान में

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आव्हान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस द्वारा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ एकजुटता में और उनकी निडर और समझौताहीन लड़ाई के समर्थन में 12 जुलाई 2023 को राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक गांधी प्रतिमा के सामने राज्यस्तरीय एक दिवसीय मौन-सत्याग्रह (मौन-विरोध) कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे राहुल गांधी जी विभिन्न मंचों पर लगातार मोदी और अडानी के संबंधों पर सवाल उठाते रहे है और उन्हें उजागर करते रहे है। उनके साहसी प्रयास ने प्रधानमंत्री और भाजपा को कुटिल कदम उठाने के लिये मजबूर कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दोषी ठहराया गया और लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद राहुल गांधी मोदी द्वारा सत्ता के दुरूपयोग के खिलाफ अपनी अजये लड़ाई और सच्चाई के लिए लडने् और देश के लोगों से संबंधित मुद्दों को उठाने में लगातार लगे हुए है। उन्होंने निडर होकर कहा कि मैं अपने देश की आवाज के लिए लड़ रहा हूं। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं।'' न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरे देश ने इस गलत सजा और अयोग्यता की निंदा की है और इस नेक लड़ाई में राहुल जी के साथ खड़े होने का संकल्प लिया है। मरकाम ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में अब समय आ गया है कि हम एक साथ खड़े हों और दोहराएं कि राहुल गांधी अकेले नहीं है और लाखों कांग्रेसी और करोड़ों लोग अपनी राजनीति संबंद्धता के बावजूद सच्चाई और न्याय की इस लड़ाई में उनके साथ है। कार्यक्रम में जिला एवं ब्लॉक स्तर के स्थानीय प्रदेश पदाधिकारियों, सांसद, पूर्व सांसद प्रत्याशी, विधायक, पूर्व प्रत्याशी, पूर्व विधायकों, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों, मोर्चा संगठन शामिल होंगे।

आदिवासी सरपंचों का हो रहा अपमान : महेश गागड़ा

बीजापुर। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया है कि क्षेत्रीय विधायक विक्रम मंडावी द्वारा कलेक्टर को पत्र लिखकर ग्राम पंचायत और सरपंचों के कार्य को क्षमता विहीन बताया। जबकि यह उनके अधिकारों का है। विधायक आदिवासी सरपंचों का अपमान कर रहे हैं। वहीं विधायक विक्रम मंडावी ने गागड़ा के आरोप को बेकार बताया है।

अपने जारी बयान में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता महेश गागड़ा ने विधायक विक्रम मंडावी पर आरोप लगाते कहा है कि विधायक अपने चेहतों के माध्यम से काम कर मोटी रकम बनाने का काम कर रहे हैं। साथ ही एक भारतीय लोक सेवा के अधिकारी भी नियम प्रक्रिया के संरक्षण और संचालन के जिम्मेदार है। गागड़ा ने कहा कि बीजापुर में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। उन्होंने इसे नियम विरुद्ध जाकर कमीशन खाने का अभियान चलाना बताया है। उन्होंने कहा कि वे इसकी निंदा करते हैं।

पूर्व मंत्री गागड़ा ने आगे कहा है कि सूबे के मुखिया पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में पंचायतों को मजबूत और सशक्त हस्ताक्षर की बात करते हैं। वहीं उनके विधायक सरपंचों और ग्राम पंचायतों का अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा पंचायतों को पचास लाख तक के कार्यों का अधिकार दिया गया है। परंतु पूरे प्रदेश में पचास लाख तक का कार्य तो दूर पांच हजार तक का काम भी इनके विधायक कर रहे हैं और सरपंच अपने आपको को बेबस होने के साथ ठगा महसूस कर रहे हैं।

वहीं बीजापुर विधायक विक्रम मन्डावी ने भाजपा नेता महेश गागड़ा द्वारा लगाए गए आरोप को गलत बताते हुए कहा कि जनता के कार्यों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को जल्द से जल्द और सुचारू रुप से कार्य करने के लिए जन प्रतिनिधियों द्वारा समय समय पर पत्र लिखा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई लाभ या निजी स्वार्थ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आगामी चुनाव में अपनी हार को देखते हुए इस प्रकार बेकार के आरोप लगा रहे हैं।

सीएसआईडीसी चेयरमेन साय पहुंचे बचेली

■ पार्षद फिरोज नवाब ने स्कूली बच्चों व बुजुर्गों के संदर्भ रखी प्रमुख मांग

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य औधोगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) के अध्यक्ष श्री नंदकुमार साय एक दिवसीय दौरे पर बचेली पहुंचे। एनएमडीसी के अधिशासी निदेशक वेंकटसरलु और कार्मिक महाप्रवधक धर्मेंद्र आचार्य,किरंदुल से जीएम पी नायक और माधव कुमार तथा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और पालिका परिषद से सभी पार्षद एवं एल्डरमैन ने जोरदार स्वागत किया।

श्री साय ने एक बैठक में एनएमडीसी के अधिकारियों और स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से चर्चा किया और एनएमडीसी के द्वारा सीएसआर और डीएमएफ फंड से आदिवासियों के हित किए जा रहे कार्यों की जानकारी से अवगत होने पर तारीफ करते हुए कहा कि अधिकाधिक लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके यह प्रयास होना चाहिए।

इस बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष संतोष दुबे, पालिका अध्यक्ष पूजा साव, उपाध्यक्ष उस्मान खान, वरिष्ठ कांग्रेसी जी एस कुमार और बबलू सिंह के साथ पार्षद फिरोज नवाब,किरण जायसवाल,वीणा साहू,रीना दुर्गा दमयंती साहू ,एल्डरमैन कमला सोनवानी,ब्रह्म सुनानी, गोपाल कश्यप, रघु और जिला कांग्रेस सचिव नरेंद्र सोनी,संजीव साव, युवा कांग्रेस से सलमान नवाब सुनील गाइन आकाश नियाल शामिल रहे।

इस बैठक से परे साय ने अलग से स्थानीय कांग्रेस प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए राज्य सरकार के कामकाज से लोगों को अवगत कराने व आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने की बात कही। नगर विकास पर उन्होने सुझाव मांगे।

नंदकुमार साय ने बचेली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर नगर में हो रहे विकास कार्य और आने वाले विधानसभा चुनाव को ले कर विशेष चर्चा किया,बचेली के जनसेवक पार्षद फिरोज नवाब ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि बचेली के डीएवी स्कूल और केंद्रीय विद्यालय के 11वीं कक्षा के बच्चों की संख्या को देखते हुए सेक्शन बढ़ाने की जरूरत है। इसके अभाव में अध्ययन के लिए प्रतिदिन 10 से 30 किलोमीटर तक की यात्रा करना पड़ता है जो आज के दौर में पूरी तरह से अनुचित है। सेक्शन बढ़ाने की व्यवस्था हो जायेगी तो इन्हे भटकना नहीं पड़ेगा।

बढ़ते शहरीकरण के बीच वृक्षारोपण की ज्यादा से ज्यादा जरूरत : सत्यनारायण शर्मा

रायपुर। महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय के एनएसएस,एनसीसी एवं नवसृजन के सदस्यों द्वारा शनिवार को वृक्षारोपण महोत्सव का आयोजन महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय के नए परिसर सेजबहार में किया गया था।

मुख्य अतिथि विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह वन संपदा केवल अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नहीं अपितु हमारे मानवीय जीवन को बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक है छत्तीसगढ़ में वनों की प्रतिशत सर्वाधिक होने के बावजूद भी तेजी से शहरीकरण हो रहा है अत- जलवायु को समायोजित करने का जिम्मा युवाओं के ऊपर सर्वाधिक है।

कार्यक्रम में अध्यक्षता करते हुए महेंद्र अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा प्रचारक समिति द्वारा संचालित महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय के विस्तार के लिए नए मापदंडों के अनुरूप महाविद्यालय का भवन, खेल मैदान आदि का होना आवश्यक है इन्हीं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ट्रस्ट की ओर से अतिरिक्त 2 एकड़ भूमि खेल मैदान के लिए दिया. कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रुप में सम्मिलित अजय तिवारी ने कहा कि महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय के 25 वर्ष में महाविद्यालय के विस्तार को देखते हुए नए भवन की आवश्यकता थी जिसे इस परिसर के माध्यम से पूरा किया गया यह परिसर भविष्य में हरा भरा परिसर के नाम से जाना-पहचाना जाएगा। उन्होंने बच्चों से आह्वान किया कि सभी बच्चे एक एक पौधे को गोद लेवें एवं प्रत्येक माह में दो बार यहां आकर उन पेड़ों का देखभाल करें .कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्काउट गाइड के अध्यक्ष श्री सुरेश शुक्ला राजू पांडे ,जे एन, अग्रवाल,महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ देवाशीष मुखर्जी, डॉ. लक्ष्मीकांत आदि उपस्थित थे।

देवगुड़ियों के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार मामले में सजा दिलवाकर रहेंगे : अजय सिंह

बीजापुर। युवा आयोग के पूर्व सदस्य अजय सिंह ने 117 देवगुडियों के निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर बीजापुर कोतवाली में एवं कलेक्टर बीजापुर को लिखित शिकायत कर पूरे मामले की सुक्ष्मता से जांच कर अविलंब कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि इतने बड़े भ्रष्टाचार में विधायक की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। अपने चहेते ठेकेदार को फायदा पहुंचाने देवगुडियों के निर्माण में जालसाजी कर काम पूरा किए बिना बड़ी रकम 01 करोड़ 39 लाख 68 हजार रूपए का भुगतान एकमुश्त ठेकेदार के खाते में डलवा दी गई। अजय सिंह का कहना है कि प्रशासन इस पर अविलंब कार्रवाई नहीं करती है तो वे पूरे मामले को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर करेंगे। दोषियों को हर हाल में सजा दिलवा कर रहेंगे।

अजय सिंह ने कहा है कि सूचना के अधिकार में इसका खुलासा हुआ है। उन्होंने बताया कि बीजापुर के एक कथित ठेकेदार के कर्मचारी को पूरी जालसाजी में मोहरा बनाकर अनिल लिंगम के नाम से फर्जी तरीके से फर्म किसान बोरबेल्स एंड सप्लायर्स को कार्यादेश जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर देवगुड़ी निर्माण कार्य हेतु संबंधित प्रगति दिखाते हुए 40 प्रतिशत राशि जारी कर दी जाती है। इतना ही नहीं उक्त निविदा जारी होने और अंतिम तिथि के बाद पंजीकृत कराए गए फर्म के नाम पर निविदा की जगह कोटेशन मंगाकर खाते में राशि आहरित कर ली गई है। उन्होने कहा कि जालसाजी में विधायक विक्रम मंडावी की संलिप्तता इसी बात से उजागर होती है, कि देवगुड़ी निर्माण के कार्यादेश के बदलने के लिए विधायक अपने लेटर हेड में कलेक्टर बीजापुर को पत्र लिखकर कार्य की प्रगति और गुणवत्ता के बहाने जनपदों को स्वीकृत देवगुड़ी निर्माण कार्य को सहायक आयुक्त विकास विभाग को निर्माण एजेंसी बनाने पत्र लिखते है, जिसके बाद जनसंपर्क विभाग के माध्यम से विज्ञापन छपवाने में गड़बड़ी करते हुए एक विज्ञापन साप्ताहिक और दैनिक अखबार में छपवाया जाता है। सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग ने एजेंसी बनाये जाने के 27 दिसंबर 2022 से पूर्व ही 26 दिसंबर 2022 को विज्ञापन जारी करना अपने आप में कूटरचना का शुरूआती पहलु दर्शाता है।

अजय के मुताबिक निविदा में जिसे काम दिया गया है, वह बीजापुर के कथित ठेकेदार जो विधायक का करीबी भी है। कर्मचारी अनिल लिंगम के फर्म किसान बोरबेल्स एंड सप्लायर्स नाम से फर्म निविदा जमा होने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2023 के बाद 03 फरवरी 2023 को जीएसटी पंजीयन कराता है। उसके बाद सहायक आयुक्त एवं कलेक्टर बीजापुर द्वारा 13 फरवरी 2023 को कार्यादेश कोटेशन पर ही मंजूर कर लिया जाता है। उसके अगले ही दिन 14 फरवरी 2023 को बैंक खाते में फर्म के नाम पर 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के आवेदन पर उसे अगले ही दिन चेक के माध्यम से सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग 62 जगहों के कार्य प्रगति पर दर्शाकर 40 प्रतिशत रकम 01 करोड़ 39 लाख 68 हजार रूपए भुगतान कर दिया जाता है। उन्होने कहा कि निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी को छिपाने के लिए आरोपियों द्वारा ऑफिस ऑफ इंजीनियर एंड चीफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ में पंजीयन कराने की कोशिश की जाती है। 17 अप्रैल 2023 को फर्म के नाम पर प्रोप्राइटर अनिल लिंगम के नाम से डी श्रेणी में पंजीयन कराया गया।

क्या बढ़ेंगे सिंहदेव के विभाग ?

सरकारी तौर पर भी स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। याने भूपेश मंत्रिमंडल में उनकी हैसियत घोषित रूप से नंबर दो हो गई है। अब चर्चा विभाग को लेकर है। टी एस सिंहदेव के पास अभी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के साथ वाणिज्यिक कर (जीएसटी) है। कहा जा रहा है कि पद के साथ टी एस सिंहदेव को कुछ विभाग भी मिलेंगे। विभाग को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। कहते हैं टी एस सिंहदेव का पसंदीदा विभाग वित्त है। 2018 में मंत्रिमंडल के बाद विभागों के बंटवारे में वे वित्त विभाग चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त अपने पास रख कर उन्हें बड़ा विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास दे दिया था , जिसे उन्होंने जुलाई 2022 में लौटा दिया। राजनीतिक हल्कों में ख़बरें चल रही हैं कि उप मुख्यमंत्री के नाते टी एस सिंहदेव को गृह विभाग दिया जा सकता है, लोगों का कहना है कि ताम्रध्वज साहू गृह विभाग छोड़ना नहीं चाहते। नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री के पास भले खास पावर नहीं है , पर %तमगा% तो बड़ा है। भूपेश सरकार के पास अब खेलने के लिए तीन महीने ही बचे हैं , ऐसे में खिलाड़ी बदलने की गुंजाइश दिखती नहीं हैं। भले ही हल्ला -गुल्ला कुछ भी हो। ताश के पत्तों की तरह विभागों को कुछ उलट -पुलट किया जा सकता है।

धनेन्द्र साहू मंत्री बनने के इच्छुक

कहते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेन्द्र साहू संगठन में कोई जिम्मेदारी संभालने की जगह सरकार में मंत्री पद चाहते हैं। चर्चा है कि पिछले दिनों कांग्रेस महासचिव और छत्तीसगढ़

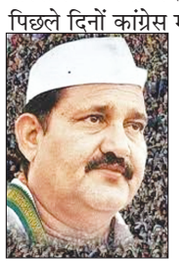

प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य नेताओं की बैठक में धनेन्द्र साहू को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर सहमति हो गई थी, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं बताए जाते हैं। धनेन्द्र साहू को संगठन और सरकार दोनों में रहने का अनुभव है। वे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और जोगी मंत्रिमंडल के सदस्य भी। कांग्रेस सरकार बनने के बाद राज्य के कई नेता अपने या अपने रिश्तेदारों के लिए पद ले चुके हैं, पर जिन इक्के-दुक्के नेताओं ने अभी तक पद नहीं लिया है, उसमें धनेन्द्र साहू शामिल हैं। कहा जा रहा है कि साहू समाज को संदेश देने के लिए धनेन्द्र साहू की टोपी में कलगी लगाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं क्या होता है ?

छत्तीसगढ़ पर पीएम-एचएम की खास नजर

कहते हैं छत्तीसगढ़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ख़ास नजर है। दोनों हर हाल में राज्य में 2023 में भाजपा की सरकार चाहते हैं। इस

रणनीति के तहत ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को सह-चुनाव प्रभारी बनाया गया है। प्रदेश प्रभारी के नाते ओम माथुर को चुनाव की कमान सौंपना वाजिब लगता है , लेकिन मनसुख मंडाविया का नाम चौकाने वाला है। नरेंद्र मोदी ,अमित शाह की तरह मनसुख मंडाविया भी गुजरात से हैं। कहा जा रहा है कि कई खेमों में बटी छत्तीसगढ़ भाजपा को मनसुख मंडाविया के माध्यम से मोदी-शाह नियंत्रित करेंगे। खबर है कि विधानसभा चुनाव तक मनसुख मंडाविया हफ्ते में दो दिन छत्तीसगढ़ में डेरा डालेंगे। वहीं अमित शाह भी अगले कुछ महीनों में एक-दो हफ्ते के अंतराल में रायपुर लैंड करते रहेंगे। अमित शाह 5 और 6 जुलाई को रायपुर में थे। अब 14 जुलाई को उनके फिर रायपुर आने की खबर है।

क्या लोकसभा और विस चुनाव एक साथ होंगे ?

छत्तीसगढ़ समेत कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए

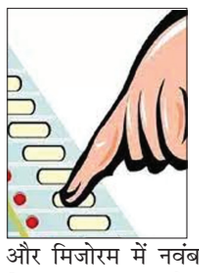

जाने की चर्चा है। हल्ला है कि लोकसभा का चुनाव मई 2024 से कुछ महीने पहले कराया जा सकता है, ऐसे में छत्तीसगढ़,राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में नवंबर 2023 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को आगे बढ़ाया जा सकता है। इन राज्यों में कुछ महीनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बात भी चर्चा में है। ओडिशा विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ ही होता है। हरियाणा विधानसभा का चुनाव भी आम चुनाव के साथ कराए जाने की ख़बरें उड़ रही हैं। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल अक्टूबर 2024 तक है। चुनाव के समय को आगे-पीछे करने पर लोकसभा चुनाव के साथ सात राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं।कहते हैं खर्च में बचत के लिए ऐसा सोचा जा रहा है, लेकिन यह सब राजनीतिक गुणा-भाग पर निर्भर करेगा। देखते हैं आगे क्या होता है ?

रमनसिंह को तव्वजो

कहा जा रहा है कि भाजपा 2023 का विधानसभा चुनाव भले डॉ रमन सिंह के चेहरे पर न लड़े, लेकिन मैदान में आगे वही रहेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गोपनीय बैठक में जिस तरह से तीन बार के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को महत्व मिला है, वह एक संकेत है। नरेंद्र मोदी के सरकारी कार्यक्रम में मंच में डॉ रमन सिंह को स्थान मिला और आमसभा में भी। अमित शाह ने भी राज्य की चुनावी रणनीति पर डॉ रमन सिंह से चर्चा की। अमित शाह ने आदिवासी नेता के तौर पर पूर्व सांसद रामविचार नेताम को बैठक में अनुमति दी, वहीं कहते हैं डॉ रमन सिंह की इच्छा पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक को अमित शाह की गोपनीय बैठक में बुलाया गया। डॉ रमन सिंह के विरोधियों को बैठक में शामिल होने के लिए इंतजार करते रहना पड़ा।

राज्य में ईडी के अगले कदम का इंतजार

ईडी ने शराब घोटाले में रायपुर के जिला कोर्ट में 13 हजार पन्ने का चालान पेश किया और इस घोटाले में शामिल लोगों के बारे में 300 पेज से अधिक का चार्जशीट भी दायर किया है। चालान और चार्जशीट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं अब ईडी के अगले कदम का इंतजार भी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि कोर्ट में चालान और चार्जशीट पेश करने के बाद अब ईडी फ्री हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में ईडी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है।

चुनावी साल में आक्रोशित कर्मचारी

चुनावी साल में राज्य के कर्मचारी महंगाई

भत्ते और अन्य मांगों को लेकर नाराज चल रहे हैं। सात जुलाई को मंत्रालय और संचालनालय समेत अन्य दफ्तरों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। मांगें पूरी न होने पर वे एक अगस्त से फिर हड़ताल पर जाने के मूड में हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के एक दिन पहले सरकार ने 5 फीसदी महंगाई भत्ता तो बढ़ाया , लेकिन बात बनी नहीं। चुनावी साल में कर्मचारी और दूसरे लोग अपनी मांगों के लिए सरकार पर दबाव तो बनाएंगे ही, पर ऐसे समय में मध्यस्थता कराने वालों की बड़ी भूमिका होती है , जिससे सांप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे। पर इस सरकार में मध्यस्थता कराने वालों की कमी नजर आ रही है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार और पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक हैं।)

भाजपा की चुनावी घोषणा पत्र समिति का ऐलान

सांसद विजय बघेल को बनाया संयोजक, अमर अग्रवाल, रामविचार होंगे सहसंयोजक

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र समिति तय कर दी है। सांसद विजय बघेल को इस समिति का संयोजक, रामविचार नेताम और अमर अग्रवाल को सह संयोजक बनाया गया है ।31 अलग-अलग नेताओं को इस घोषणापत्र समिति में सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है।

विजय बघेल, संयोजक दुर्ग, रामविचार नेताम सहसंयोजक सरगुजा, अमर अग्रवाल सहसंयोजक बिलासपुर, शिवरतन शर्मा सहसंयोजक बलौदाबाजार, सुश्री लता उसेण्डी सदस्य, कोण्डागांव, चंद्रशेखर साहू सदस्य रायपुर, कृष्णमूर्ति बांधी सदस्य बिलासपुर, राजा रणविजय सिंह सदस्य जशपुर, मधुसूदन यादव सदस्य राजनांदगांव, श्रीमति रंजना साहू सदस्य धमतरी, भैयालाल राजवाड़े सदस्य कोरिया, महेश गांगड़ा सदस्य रायपुर, कमलभान सिंह सदस्य सरगुजा, कमला देवी पाटले ,सदस्य जांजगीर-चांपा, ओपी चौधरी सदस्य रायगढ़, चम्पा देवी पाटले सदस्य मनेंद्रगढ़ -चिरमिरी-भरतपुर, संदीपशर्मा सदस्य रायपुर, केदारगुप्ता सदस्य रायपुर, भरतवर्मा सदस्य राजनांदगांव, रविभगत सदस्य रायगढ़, विभाग अवस्थी सदस्य गरियाबंद, डा. विजयशंकर मिश्रा सदस्य रायपुर, रामलखन सिंह पैकरा सदस्य बलरामपुर, पंकज झा सदस्य रायपुर, दीपक साहू सदस्य दुर्ग, आत्मनारायण पटेल सदस्य कोरबा, श्रीरामकृष्ण धीवर सदस्य कवर्धा, द्वारिका जायसवाल सदस्य मुंगेली, टेकेश्वर जैन सदस्य कांकेर, विक्रम सिंह सदस्य बिलासपुर आदि सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग की बड़ी पहल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में यात्री बसों में महिलाओं एवं स्कूल बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पैनिक बटन लगाने की तैयारी है। पैनिक बटन लगने से बस में किसी प्रकार की दुर्घटना, छेड़छाड़ होने पर पैनिक बटन दबाने से तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना मिल जाएगी। इसके साथ ही बसों का लोकेशन, स्पीड आदि का भी पता चलता रहेगा। इससे चालकों की मनमानी पर रोक लगने के साथ हादसे की आशंका भी कम हो जाएगी। जीपीएस सिस्टम का कंट्रोल रूम डायल 112 के कार्यालय में बनाया गया है।

परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस व्यवस्था के शुरू होने से जनता को किसी तरह के खतरे तथा अनहोनी से निपटने में काफी सहूलियत होगी। वर्तमान में प्रदेश में कुल 12 हजार बसें संचालित हो रही हैं, जो अलग-अलग रूट से प्रदेश के कोने-कोने तक जा रही हैं। इसी तरह राज्य में लगभग 6000 स्कूल बस भी संचालित है। बसों में पैनिक बटन और जीपीएस के लगने से बसों की पल-पल की जानकारी मिलेगी।

गौरतलब है कि राज्य में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा सुगम यातायात व्यवस्था के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे है। इस संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नवीन व्यवस्था के तहत स्कूल बस के रूट में भी मैप रहेगा ताकि स्कूल बस यदि बच्चों को लेकर निर्धारित रूट के अलावा कहीं जाये तो ऑटोमैटिक अलर्ट आ जाये।

रीपा में ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा रोजगार, हो रहा सकारात्मक बदलाव

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) योजना से गांवों में ग्रामीणों को रोजगार व स्व-रोजगार के अवसर मिलने लगे हैं। महिलाएं आत्मनिर्भरता की राह में अग्रसर हो रही हैं। गांवों को उत्पादन का केन्द्र और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई यह योजना अब ग्रामीण परिदृश्य में एक सकारात्मक बदलाव लाने लगी है। ग्रामीणजन रीपा के माध्यम से अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में बदलाव के लिए पूरे मनोयोग से जुट गए हैं।

गरियाबंद ज़िले के फिंगेश्वर ब्लॉक में ग्राम पंचायत श्यामनगर स्थित रीपा में सिलाई यूनिट की स्थापना की गई है। यूनिट की स्थापना से लगभग 50 ग्रामीणों को रोज़गार मिला है, साथ ही यहां

कार्यरत् महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए 14 हजार यूनिफार्म सिलाई का आर्डर दिया है। रीपा में समूह के सदस्यों द्वारा हथकरघा, अगरबत्ती निर्माण, धोबी का भी कार्य किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने, लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) योजना प्रारंभ किया गया है। राज्य सरकार द्वारा छोटे-छोटे उद्योग धंधों के लिए रीपा में पानी, बिजली, जमीन जैसी सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। रीपा के माध्यम से गांव के लोगों को जरूरी वस्तुएं आस-पास उपलब्ध हो रही हैं, जिसके कारण अब उन्हें दूर शहरों की ओर नहीं जाना पड़ता। उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता के कारण आसपास के शहर-गांवों से सप्लाई के आर्डर मिलने प्रारंभ हो गए हैं। व्यवसायिक गतिविधियों को रीपा के साथ जोड़कर संरक्षित करने के साथ ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर विभिन्न गतिविधियां संचालित होने से लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी प्राप्त हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

विकास की गारंटी वाली सरकार आयेगी: चौधरी

रायपुर। भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार की गारंटी की सरकार चलाने वाले भूपेश बघेल जी आपको याद दिला दें कि जब केंद्र में भाजपा की सरकार थी तो कांग्रेस के विरोध के बावजूद छत्तीसगढ़ का

निर्माण अटल बिहारी वाजपेई जी ने किया किया। भाजपा ने छत्तीसगढ़ का वास्तविक अर्थों में कल्याण किया।

साडे 4 वर्ष पूर्व कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आपने जो गारंटी दी, वह भ्रष्टाचार की गारंटी है।छत्तीसगढ़ की हजारों बहन बेटियों माताओं के सुहाग उजाड़ कर कांग्रेस 2 हजार करोड़ के शराब घोटाले की गारंटी दी है। हजारों करोड़ रुपए के कोयला घोटाले की गारंटी भूपेश सरकार ने दी है। गरीबों के 16 लाख आवास रोक कर रखने की गारंटी आपने दी है। इसे कांग्रेस के भ्रष्टाचारी पंजे से मुक्त कराने की गारंटी भाजपा की है। गरीबों को पक्का छत देने की गारंटी मोदी जी की है। गरीबों का चावल कांग्रेस के पंजे ने रोक कर रखा है उसे भी कांग्रेस के पंजे से छीन कर गरीब के पेट तक पहुंचाने की गारंटी भाजपा की है। आपकी भ्रष्टाचार की गारंटी वाली कांग्रेस सरकार जाएगी और मोदी जी की विकास की गारंटी वाली भाजपा सरकार आएगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने मुख्यमंत्री के कटाक्ष पर पलटवार करते हुए कहा सभी छत्तीसगढ़िया बोरे बासी खाते हैं।

देश में कांग्रेस का राज होता तो लग जाता आपातकाल: कश्यप

रायपुर। प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखने पर रायपुर में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं के धरना प्रदर्शन को कांग्रेस की तानाशाही प्रवृत्ति का ताजा उदाहरण बताते हुए कहा है कि कांग्रेस

का संविधान, संवैधानिक संस्थाओं और संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर पर न तो विश्वास रहा है और न ये इनका सम्मान करते। कांग्रेस एक परिवार को संविधान से ऊपर समझती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाले देश में अधिनायकवाद चलाती रही है। महामंत्री केदार कश्यपने कहा आज अगर देश की सत्ता में कांग्रेस काबिज होती तो राहुल को अदालत से दो साल की सजा मिलने पर देश में आपातकाल लगा दिया जाता। राहुल की दादी इंदिरा गांधी ने यही किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया तो कानून का पालन करने की बजाय लोकतंत्र को कुचलकर देश पर आपातकाल थोप दिया था। कांग्रेस इस परिवार की करतूतों पर परदा डालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।

प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि एक चार्जशीटेड मुख्यमंत्री ने अपने सियासी कुनबे के साथ बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने अपने सजा प्राप्त आका के समर्थन में जो कुछ भी कहा, वह अदालत का अपमान है। उच्च न्यायालय ने राहुल की याचिका खारिज करते हुए साफ कहा है कि उनके विरुद्ध दस मामले पेंडिंग हैं।

पहली बार चुनाव अभियान की कमान बाहरी नेता के हाथों: ठाकुर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश के नेताओं पर भरोसा नहीं है। भाजपा संगठन में कई गुट है कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी है जनता का समर्थन खो चुके हैं इसीलिए संगठन से लेकर चुनाव की सारी

जिम्मेदारियों को प्रदेश के बाहर से नेता भेजकर पूरा कर रहे हैं। भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व को स्थानीय नेताओं पर नहीं है भरोसा माथुर, मांडविया को बनाया चुनाव प्रभारी। पहली बार चुनाव अभियान की कमान प्रदेश के बाहर के नेताओं को मिली है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सारे अपनी विश्वसनीयता खो चुके है ये खुद की दावेदारी सुरक्षित रखने संघर्ष कर रहे है। राज्य के बाहर के लोगो को चुनाव प्रभारी बनाया जाना छत्तीसगढ़ के नेताओं की अयोग्यता को दिखाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा में भी रमन सरकार के खासमखास सिपहसालार से लेकर उस दौर में कद्दावर और ताकतवर मंत्री माने जाने वाले कई मठाधीश नेताओ को मचं से उतारा गया कुछ की फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। 15 साल के रमन सरकार के दौरान पूरे प्रदेश की जनता हताश और परेशान थी हर विभाग में हर योजना में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार था।

रविवि में भाजपा का झंडा एनएसयूआई ने जताई आपत्ति कुलपति से मिले

रायपुर। प्रधानमंत्री मोदी के 7 जुलाई को रायपुर दौरे के दौरान रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर में भाजपा का झंडा लगाए जाने पर एनएसयूआई ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक हनी बग्गा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में एनएसयूआई ने बीजेपी का झंडा लगने पर अपना विरोध दर्ज कराया और कहा कि जिस प्रकार विश्वविद्यालय परिसर में बीजेपी का झंडा लगाया गया इसका हम विरोध करते हैं और बीजेपी पर कार्यवाही की मांग करते हैं। यदि विश्वविद्यालय बीजेपी पर उचित कार्यवाही नहीं करती है तो एनएसयूआई को लिखित रूप से यह सूचना देगी। आने वाले समय में कांग्रेस के नेता जो संविधानिक पद पर बैठे हैं जब वह विश्वविद्यालय परिसर में आए तब हम कांग्रेस पार्टी का झंडा विश्वविद्यालय परिसर में लगाएं। इस बात को कहते हुए उन्होंने कुलपति से लिखित रूप से इसकी मांग की। राष्ट्रीय संयोजक हनी बग्गा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइंस कॉलेज मैदान में सरकारी एवं पार्टी के कार्य से रायपुर में एक दिवसीय दौरे पर आए थे। विश्वविद्यालय परिसर के अंदर से होते हुए वे कार्यक्रम स्थल पहुंचे। यह विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक गौरव का विषय है पर। जिस प्रकार विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर बीजेपी के झंडे लगाए गए वह पूर्णत: गलत है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी पार्टी विशेष का झंडा नहीं लगना चाहिए। इसको लेकर हमने कुलपति को ज्ञापन दिया।

घायल भाजपा कार्यकर्ता को किया गया एयरलिफ्ट

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सभा में शामिल होने सूरजपुर से रायपुर जा रहे हैं बस हादसे में अत्यंत ही गंभीर रूप से घायल कार्यकर्ता घायल भाजपा कार्यकर्ता विश्वंभर यादव को आज चकरभाठा एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस के द्वारा दिल्ली एम्स अस्पताल के लिए शिफ्ट कर दिया गया विश्वंभर यादव को रीढ़ की हड्डी में गहरी चोंट आई और जल्द से जल्द जिसका ऑपरेशन किया जाना है अत: चिकित्सकीय परामर्श व परिजोनों से राय मशविरा कर आगे की चिकित्सा दिल्ली के एम्स अस्पताल में कराने की सहमति बनीं है इस लिहाज से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी एवं पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल आज सुबह-सुबह अपोलो अस्पताल पहुंच कर घायल कार्यकर्ता विश्वंभर को तत्काल एंबुलेंस से चकरभाठा एयरपोर्ट के लिए रवाना किया और दोपहर 3.00 बजे उन्हें दिल्ली के लिए एयर लिफ्ट कर लिया गया इस बाबत केंद्रीय स्वस्थ मंत्री द्वारा दिल्ली एम्स अस्पताल को अलर्ट कर दिया गया है ज्ञात हो कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व इस घटना को लेकर अत्यंत ही संवेदनशील हैं वे घायलों के परिवार से संपर्क बनाएं हुए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडावी एवम केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह घटना के बाद से ही पीड़ित कार्यकर्ताओं परिजनों से लगातार बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका जी ने तों अपने एक निजी स्टाफ को भी नियुक्त कर रखा हैं बिलासपुर जिला के वरिष्ठ नेताओं व प्रमुख पदाधिकारि घायलों के देखरेख में लगे हुएं हैं हादसे में घायल लीलू गुप्ता जिनके पसली और आंत में चोट आई है।

असौंदावासियों का अवैध शराब के खिलाफ मोर्चा जारी

- **कोचियों को अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन**

रायपुर । बीते रविवार से अवैध शराब बिक्री के खिलाफ असौंदावासियों का मोर्चा लगातार जारी है। किसानी के इस व्यस्त मौसम में भी वे रोज रैली निकाल चौकसी करने के साथ-साथ कोचियो को भी समझाईश दे रहे हैं । इस असामाजिक कृत्य से तौबा कर लेने की कोचियो को दिया गया अल्टीमेटम का कल रविवार को अंतिम दिन है। ग्रामीण सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 3 कोचिये अभी भी चोरी छिपे अवैध शराब बेच रहे हैं। सर्वाधिक दिलचस्प बात तो यह है कि ग्रामीणों द्वारा मोर्चा खोलने के इतने दिन बाद भी शासन - प्रशासन का कोई जिम्मेदार नुमाइंदा अभी तक असौंदा नहीं पहुंचा है।

ज्ञातव्य हो कि खरोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लगभग 1600 की आबादी वाले इस ग्राम में तकरीबन 8-10 शराब कोचिये गली कूचों में सक्रिय

थे जिसकी वजह से न केवल ग्राम का माहौल खराब था वरन् असौंदा सड़क मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसी के परिप्रेक्ष्य में बीते रविवार को असौंदा के ग्रामीणों व आसपास के ग्राम प्रमुखों की बैठक आहूत की गयी थी। बैठक में इसके खिलाफ मोर्चा खोलने के निर्णय के साथ - साथ कोचियो को आसन्न रविवार तक इस असामाजिक कृत्य से तौबा कर लेने हेतु समय देने सहमति बनी थी । बैठक में शराब के खिलाफ ग्रामीणों के आक्रोश व एकजुटता को देखते हुये ग्रामीणों ने महिलाओं को समर्थन दे उनके साथ मोर्चा खोल दिया था और तब से खेती के इस व्यस्त मौसम में भी रोजाना रैली निकाल चौकसी करने के साथ-साथ कोचियो को भी समझाईश दे रहे हैं।

ग्रामीण सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम में खुले आम अवैध शराब बिक्री का धंधा तो बंद हो गया है पर 2 - 3 कोचिये अभी भी गुपचुप रुप से अवैध शराब बेच रहे हैं और एक कोचिया द्वारा तो ग्राम के बाहर भाठापारा शाखा नहर में असौंदा के नहर पार में शराब बेचना शुरू कर दिया है जहां शाम ढले पियक्कड़ों की भीड़ जुट रही है । ग्रामीणों को इसकी भनक लग गयी है और वे इन कोचियो को समझाईश पर समझाईश देने के साथ उनको दिये गये अल्टीमेटम के अंतिम दिन बीतने का इन्तजार कर रहे हैं।

अल्टीमेटम की अवधि खत्म होने के बाद वे समीक्षा कर आगामी रुख़ का निर्णय करेंगे । इधर शराब विरोधी मुहिम में जुटे किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा को असौंदा व प्रभावित आसपास के ग्रामों के ग्राम प्रमुखों द्वारा लगातार आद्यतन जानकारी पहुंचाया जा रहा है व वे उन्हें गांधीवादी तरीके से संघर्ष जारी रखने प्रोत्साहित कर रहे हैं । सरपंच राजेश साहू सहित वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों , पूर्व सरपंचद्वय जितेन्द्र चंद्राकर व राजू टंडन , सिंचाई पंचायत के अध्यक्ष रहे मुरारी वर्मा व ग्राम प्रमुखों ने विश्वास व्यक्त किया है कि लगातार समझाईश के चलते अल्टीमेटम की अवधि समाप्ति के बाद लिप्त तत्वों द्वारा जनभावना का सम्मान करते हुये अवैध शराब बिक्री बंद कर दिया जावेगा और आगे कोई कार्यवाही का मौका नहीं देंगे।

कर्मचारियों के विरुद्ध भी कांग्रेस का दमनकारी रवैया निंदनीय : शर्मा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने प्रदेशभर में अधिकारियों और कर्मचारियों की चल रही हड़ताल को लेकर प्रदेश सरकार के संवेदनहीन रवैए की कड़ी आलोचना की है। विजय शर्मा ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में किए गए वादे अब तक पूरा नहीं करने वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार का पूरा शासनकाल हड़ताल और प्रदर्शनों में बीत गया। प्रदेश सरकार की इसी संवेदनहीनता ने आज प्रदेश के सारे कार्यों को ठप कर रखा है और जरूरतमंदों को अकारण

परेशानी उठानी पड़ रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी महासंघ से संबद्ध 25 हजार अफसर-कर्मियों की हड़ताल से शुक्रवार को 52 विभागों में कामकाज ठप रहा। इसके चलते न तो दफ्तर खुले, न रोजगार कार्यालय में पंजीयन का काम हुआ और न ही जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र बने। इससे पहले लगभग एक सप्ताह से संविदा कर्मचारी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.